अप्रैल, 2023, वर्ष : 44 अंक : 04 www.indiatibet.net

तिब्बत की पहली हिन्दी समाचार पत्रिका

तिब्बत देश

तिब्बती अपहृत बालक। पेंछेन लामा गेंदुन छोक्यि जिमा।

मूल्य :10 रू , वार्षिक : 100 रू

अप्रैल, 2023, वर्ष : 44 अंक : 04

तिब्बत देश

तिब्बत की पहली हिन्दी समाचार पत्रिका पहली बार 1979 में प्रकाशित तिब्बत के बारे में सही जानकारी के साथ हर महीने आपके हाथो में

वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन में परम पावन दलाई लामा।

प्रधान संपादक
जमयंग दोरजी

सलाहकार संपादक
प्रो. श्यामनाथ मिश्र , डा. अतुल कुमार

प्रबंध संपादक
तेनजिन जोरदेन, ताशी देकि

वितरण प्रबंधक
छोन्यी छेरिंग

संपादकीय एवं प्रकाशन कार्यालय :
भारत तिब्बत समन्वय केन्द्र
एच -१० लाजपत नगर -३
नई दिल्ली -११००२४, भारत

तिब्बत देश में प्रकाशित विचरों से संपादक, प्रकाशक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

इसमें प्रकाशित सामग्री का उपयोग अन्यत्र किया जा सकता है। कृपया तिब्बत देश का उल्लेख अवश्य करें ।

समाचार -

- वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन- २०२३ 1
- सिक्योंग इंग्लैंड में अपने कार्यक्रमों के सिलसिले में लंदन पहुंचे 2
- तिब्बत से चोरी हुए बच्चे ११वें पंचेन लामा की ३४वीं जयंती पर डीआईआईआर का बयान 3
- सिक्योंग ने ब्रिटेन के पार्लियामेंटरी ग्रुप फॉर तिब्बत के साथ चीन-तिब्बत संघर्ष पर चर्चा की और इंटरनेशनल फ्रीडम ऑफ रिलिजन ऑर बिलीफ के समक्ष गवाही दी 4
- क्रॉस पार्टी ग्रुप ऑन तिब्बत के सदस्यों द्वारा स्कॉटिश संसद में सिक्योंग की मेजबानी 5
- ऑस्ट्रेलिया के ऑल पार्लियामेंट्री ग्रुप फॉर तिब्बत का प्रतिनिधिमंडल परम पावन दलाई लामा और सीटीए नेतृत्व से मुलाकात की 6
- १६वें कशाग ने विजन पेपर- सिक्योरिंग तिब्बत्स फ्यूचर- लॉंच किया 7
- चीनी अधिकारी तिब्बत में आत्मदाह करने वाले प्रदर्शनकारियों के रिश्तेदारों के पीछे पड़े हैं 8
- सड़कों की सफाई अभियान के दौरान ल्हासा में रेहड़ी-पटरी वाले तिब्बती निशाने पर रहे 9
- संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ चीन द्वारा तिब्बत में व्यापक श्रम शोषण से चिंतित 10

समाचार -

- भारत-तिब्बत मैत्री संघ की बिहार इकाई ने स्वर्गीय रामचंद्र खान स्मृति व्याख्यान के तहत तिब्बत मुक्ति साधना में भारतीयों की भूमिका पर चर्चा की 11
- भारत ने विवादित सीमा के पास चीन द्वारा स्थानों के नाम बदलने को खारिज कर दिया 12
- ऑस्ट्रेलियाई संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रेस कांफ्रेंस में तिब्बत मुद्दे पर समर्थन जारी रखने का आश्वासन दिया 13
- फ्रांसीसी सीनेट का चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पांच दिवसीय दौरे पर धर्मशाला पहुंचा 14
- प्रतिनिधि डॉ. आर्य ने जी ७ नेताओं से तिब्बत में अधिकारों के उल्लंघन के लिए चीन की निंदा करने वाले बयान जारी करने की अपील की 15
- जर्मनी ने तिब्बत में सभी अनिवार्य आवासीय स्कूलों को बंद करने का आह्वान किया 16
- विशेषज्ञों ने जी-७ नेताओं से तिब्बत में औपनिवेशिक आवासीय स्कूलों को बंद करने के लिए शी जिनपिंग से अनुरोध करने का आग्रह किया 17
- चीन की बढ़ती असुरक्षा की ऐतिहासिक जड़ें और समकालीन अभिव्यक्तियां 18
- संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों का कहना है कि चीन द्वारा 'व्यावसायिक प्रशिक्षण' तिब्बती पहचान को खतरे में डालनेवाला और तिब्बत में जबरन श्रम के खतरे वाला है 19

मुद्रक एवं प्रकाशक जमयांग दोरजी द्वारा प्रेम गुलाटी , डोली ऑफसेट प्रिंटर्स , डी -१५२ , एफ. एफ. सी. ओखला , नई दिल्ली -११००२० से मुद्रीत

तिब्बत के बारे में नियमित जानकारी के लिए भारत - तिब्बत समन्वय केन्द्र की वेबसाइट
www.indiatibet.net
Email:
indiatibet7@gmail.com

अपनी बात

◆ भारत के व्यापक हित में है तिब्बत समस्या का शीघ्र समाधान

तिब्बत समस्या का हल भारत के हित में है। चीन के अवैध नियंत्रण में तिब्बत के जाते ही भारतीय सुरक्षा, समृद्धि, शांति तथा स्वाभिमान पर जो संकट आया वह लगातार गहराता जा रहा है। विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़े भारतीय राजनेताओं और विशेषज्ञों ने बार-बार विस्तारवादी चीन की साजिश से हर समय सावधान किया था। उनका स्पष्ट मत था कि तिब्बत में चीनी घुसपैठ का भारत सरकार द्वारा विरोध होना चाहिये। इस विषय में भारत सरकार की चुप्पी से भारत की भौगोलिक एकता-अखंडता को भारी क्षति निश्चित है। बाबा साहब अम्बेडकर, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉ. राम मनोहर लोहिया, सरदार पटेल तथा जे.बी. कृपलानी समेत अनेक विचारक इस बिन्दु पर एकमत थे। लेकिन तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू ने तिब्बत का साथ नहीं दिया। इस भूल का दण्ड आज भी भारत भुगत रहा है।

तिब्बत पर अवैध नियंत्रण की साजिशपूर्ण प्रक्रिया के समय चीन सरकार का शीर्ष नेतृत्व नेहरू के साथ पंचषील समझौता कर रहा था। हिन्दी-चीनी भाई-भाई के नारे लग रहे थे। इससे प्रभावित प्रधानमंत्री नेहरू शांति के प्रतीक सफेद कबूतर उड़ा रहे थे, जबकि अपनी कुटिल योजनानुसार चीन युद्ध की तैयारी कर रहा था। चीन के हाथों 1962 में भारत की हार इसी का उदाहरण है।

नेहरू ने 1955-56 के बाद भूल सुधार की थोड़ी कोशिश जरूर की थी। देर से ही सही, भारत-तिब्बत के हजारों साल पुराने संबंध उन्हें याद आये और 1959 में चीनी विरोध के बावजूद उन्होंने तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु तथा राजप्रमुख परम पावन दलाई लामा को उनके हजारों अनुयायियों समेत भारत में शरण प्रदान कर दी। भारत पर चीनी आक्रमण का एक कारण इस भूल सुधार को भी बताया जाता है। भारत को उसी समय तिब्बत का साथ देना चाहिये था जब स्वतंत्र तिब्बत को चीन ने अपना भूभाग बताया था। खेतड़ी (राजस्थान) के प्रसिद्ध राजनेता और समाजसेवी कालीचरण गुप्ता बताते हैं कि ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार तिब्बत एक स्वतंत्र देश था, जो भारत एवं चीन के बीच स्थित बफर स्टेट (मध्यस्थ राज्य) था। भारत की सीमा तिब्बत से जुड़ी थी, न कि चीन से। चीन की सीमा चीन की दीवार है। इस दीवार के बाहर का भूभाग अवैध चीनी कब्जा है। सही समय पर सही निर्णय लेने में प्रधानमन्त्री नेहरू की चूक का परिणाम है कि 1959 में स्वतंत्र तिब्बत और उसके बाद 1962 में बहुत बड़ा भारतीय भूभाग चीन के अवैध नियंत्रण में चला गया।

पहले की तरह भारत एवं चीन के बीच विश्वसनीय संबंध बनाने के लिये कालीचरण गुप्ता प्रामाणिकता के साथ बताते हैं कि स्वतंत्र तिब्बत के होते भारत एवं चीन के बीच कोई सीमा विवाद नहीं था। दोनों के बीच युद्ध भी नहीं हुए थे, जबकि अब हर समय दोनों के बीच युद्ध की स्थिति बनी रहती है। भारतीय संसद के सर्वसम्मत संकल्प, जो कि 14 नवंबर, 1962 का है, कि हम भारतीय भूभाग को चीनी नियंत्रण से मुक्त करायेंगे के विपरीत चीन सरकार नये-नये भारतीय भूभागों पर अवैध दावे करती है तथा वहाँ घुसपैठ करती है। अरुणाचल प्रदेश में स्थानों, गाँवों आदि के नामों का वह चीनीकरण कर रही है। उसकी कोशिश भारत को अपमानित करने, कमजोर करने तथा चौतरफा घेरने की है।

चीन सरकार अपनी भारत विरोधी गतिविधियों का संचालन मुख्यतः तिब्बती क्षेत्र से करती है। चीन सरकार को पता है कि वास्तविक प्रमाणों को नष्ट कर या बनावटी प्रमाणों के बल पर वह तिब्बत को अपना भूभाग नहीं बना सकती। इसीलिये वह तिब्बत को बर्बाद कर रही है। तिब्बत की प्राकृतिक संपदा और पर्यावरण के विनाश से भारत की प्राकृतिक संपदा और पर्यावरण का विनाश हो रहा है। वहाँ के ग्लेसियर्स (हिमनद) से सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज आदि नदियाँ निकली हैं। इनकी धारायें मोड़कर तथा इन पर बड़े बांध बनाकर चीन सरकार भारत में अपनी आवश्यकतानुसार बाढ़ एवं सूखा ला सकती है। तिब्बत में परमाणु कचरे को गाड़ने से उसकी रेडियोधर्मिता भारत में भी पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है। चीनी वस्तुओं की तस्करी जारी है। चीनी हथियार भारत में आतंककारियों को उपलब्ध कराये जा रहे हैं। सब हो रहा है तिब्बती क्षेत्र से।

चीन सरकार भारत में भी एक ऐसी चीन समर्थक लॉबी संचालित कर रही है जिसमें भारत के तथाकथित बड़े राजनेता, पत्रकार, कलाकार, स्वयंसेवी संगठन तथा विचारक शामिल हैं। यह तिब्बती तथा भारतीय हितों को समान रूप से दुष्प्रभावित करेगी। चीन की विस्तारवादी नीति का समर्थन इसका कार्य है। भारत स्थित तिब्बत समर्थक व्यक्तियों एवं संगठनों का दायित्व है कि वे ऐसी चीन समर्थक लॉबी को बेनकाब करें। तिब्बत में मानवाधिकारों का व्यापक पैमाने पर हनन हो रहा है। वहाँ धार्मिक-सांस्कृतिक स्थल विकृत और नष्ट किये जा रहे हैं। इनका विरोध होना चाहिये। भारत सरकार को चाहिये कि वह जी-20 के विभिन्न कार्यक्रमों में चीनी प्रतिनिधियों के साथ शिष्टाचारपूर्ण से ज्यादा यथोचित व्यवहार करे। शत्रुतापूर्ण व्यवहार वाले से हाथ मिलाना जरूरी नहीं है। उसे दूर से ही नमस्कार करें।

भारत सरकार भारतीय राष्ट्रीय शक्ति का निरंतर विकास करे और कभी-कभी उसे प्रदर्शित भी करे जैसा कि उसने डोकलाम, गलवान घाटी तथा अरुणाचल प्रदेश में भी किया है। अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना हमारा कर्तव्य है। उससे भी अधिक जरूरी है वहाँ समस्त बुनियादी संसाधनों और संरचना का सुव्यवस्थित विस्तार।

प्रो0 श्यामनाथ मिश्र
पत्रकार एवं अध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खेतड़ी (राजस्थान)

मो.-9079352370, 8764060406
E-mail & Facebook: - shyamnathji@gmail.com

◆ वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन- २०२३

dalailama.com /२१ अप्रैल, २०२३

नई दिल्ली, भारत। परम पावन दलाई लामा जब वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन- २०२३ में हिस्सा लेने २१ अप्रैल की सुबह नई दिल्ली के अशोका होटल पहुंचे तो उनका स्वागत अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ (आईबीसी) के महानिदेशक डॉ अभिजीत हलदर और आईबीसी के महासचिव श्रद्धेय डॉ धम्मपिया ने किया। शिखर सम्मेलन के आयोजकों ने परम पावन को सभागार तक ले जाने के लिए एक गोल्फ कार्ट की व्यवस्था की थी। जब परम पावन ने कमरे में प्रवेश किया तो पूरी सभा उनके सम्मान में खड़ी हो गई।

परम पावन मंच पर सबसे पहले वहां स्थापित बुद्ध की मूर्ति के समक्ष जाकर नतमस्तक हुए। इसके बाद, उन्होंने मंच पर उपस्थित विभिन्न गणमान्य बौद्ध व्यक्तियों का अभिवादन किया। अपने आसन की ओर बढ़ते हुए वहां बैठने से पहले उन्होंने हॉल में एकत्रित लोगों को प्रणाम किया।

मंच पर परम पावन की बाईं ओर परम पावन भिक्षु खंबा लामा गब्जू चोइजामत्सडेम्बरेल (मंगोलिया), चामगोन केंटिंग ताई सितुपा (तिब्बत), श्रद्धेय भिक्षु धम्म शोभन महाथेरो (नेपाल) और परम पवित्र थिच थिएन टैन (वियतनाम) बैठे थे। उनकी दाहिनी ओर परम आदरणीय वास्कादुवे महिंदवांस महानायके थेरो (श्रीलंका), परम आदरणीय अभिधजमहारहथागुरु सयादव डॉ अशिन न्यानिसारा (बर्मा), परम पावन ४३वें शाक्य त्रिज़िन, खोंडुंग ज्ञान वज्र रिनपोछे (तिब्बत), महामहिम पद्म आचार्य कर्म रंगडोल (भूटान), महामहिम क्याब्जे योंगज़िन लिंग रिनपोछे तेनज़िन लुंगटोकथिनलेचोफाक (तिब्बत) औरश्रद्धेयडॉ. धम्मपिया (भारत) बैठे।

श्रद्धेय डॉ धम्मपिया ने परम पावन, आदरणीय अतिथियों और श्रोताओं का स्वागत करते हुए प्रातः की कार्यवाही शुरू की। उन्होंने कहा कि कल, शिखर सम्मेलन ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में विकसित हुई विभिन्न बौद्ध परंपराओं के बारे में सुना। इनमें से प्रत्येक बुद्ध शाक्यमुनि की शिक्षा रूपी एक ही मूल से उगने वाले अलग- अलग रंग के फूल की तरह हैं। बुद्ध ने अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग क्षमता के अलग-अलग लोगों को अलग-अलग शिक्षाएं दी।

उन्होंने सुझाव दिया कि बौद्ध संघ के सभी समुदायों को आज दुनिया में हमारे सामने मौजूद चुनौतियों का समाधान करने के लिए आगे आने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हम सभी इंसान हैं। हम एक- दूसरे से इतने अलग नहीं हैं। हम एक ही हवा और एक ही पानी का उपयोग करते हैं। इसलिए, हमें विश्व शांति को बढ़ावा देने, धरती माता की रक्षा करने और करुणा की साधना करने के लिए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाना होगा। हम सभी की मदद के लिए हमें सभी धार्मिक परंपराओं में निहित सार्वभौमिक मूल्यों को अपनाने करने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा, 'आइए, सभी प्राणियों के कल्याण और आनंद के लिए बुद्ध की शिक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए और सामंजस्यपूर्ण एकता में काम करने के लिए हाथ मिलाएं।'

संचालक कर्नल राजेश जिंदल ने थेरवादिन भिक्षुओं के एक समूह का परिचय कराया, जिन्होंने पाली में शुभ श्लोकों का पाठ किया। उनके बाद संस्कृत परंपरा के भिक्षुओं ने तिब्बती में जाप किया।

जिंदल ने बताया कि परम आदरणीय अभिधजामहरथागुरु सयादव डॉ. अशिन न्यानिसार (बर्मा) को बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हो सके। उनकी ओर से उनका संदेश पढ़ा गया। इसमें उन्होंने एक अच्छे हृदय के विकास और उसमें निहित प्रेम, करुणा और क्षमा के गुणों पर बल दिया।

उन्होंने कहा कि अगर लोगों के दिलों में शांति नहीं है तो दुनिया में शांति नहीं होगी। दिलों की शांति को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका अंतर्दृष्टि ध्यान की साधना करना है। जिस प्रकार करुणा का विकास हमें एक नकारात्मक मन को सकारात्मक में बदलने में सक्षम बनाता है, उसी तरह ध्यान हमें एक संतुलित मन प्राप्त करने में मदद करता है। परम आदरणीय का संदेश इस कामना के साथ संपन्न हुआ कि दुनिया भर में शांति और सद्भाव कायम रहे।

कर्नल जिंदल ने शिखर सम्मेलन में बौद्ध धर्म के अकादमिक अध्ययन का प्रतिनिधित्व करने के लिए परम पावन दलाई लामा के एक बहुत पुराने शिष्य प्रोफेसर रॉबर्ट थुरमन का परिचय कराया। थुरमन ने अपने वक्तव्य को इस निवेदन के साथ प्रारंभ किया कि वह परम पावन के सामने बोलने में थोड़ा डरा हुआ महसूस कर रहे हैं। हालांकि अवलोकितेश्वर की प्रार्थना करके उन्होंने इसकी भरपाई कर दी। उन्होंने कहा कि परम पावन यह भी घोषणा कर चुके हैं कि विश्व शांति आंतरिक शांति से आती है और लोगों को ऐसी शांति प्राप्त करने के तरीकों के बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता है।

थरमन ने याद किया कि कल शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की थी कि भारत ऐतिहासिक रूप से अहिंसा के समर्थन में यानि, कोई नुकसान नहीं करने के लिए समर्पित रहा है। यह महत्वपूर्ण है जब लोगों की जान लेने के बजाय खुद के मरने को तैयार होने की बात आती है। थरमन ने उल्लेख किया कि बुद्ध का जन्म एक योद्धा परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने मन में अस्पष्टता को दूर करने के लिए उस तरह का जीवन त्याग दिया।

नालंदा जैसे महान भारतीय विश्वविद्यालयों ने शिक्षा के लिए एक दृष्टिकोण विकसित किया, जिसने प्रतिभागियों को वास्तविकता की प्रकृति को समझने में सक्षम बनाया और मनोविज्ञान के संदर्भ में यह बताया कि मन को कैसे बदलना है। नालंदा के मुख्य पाठ्यक्रम को गदेन, डेपुंग और सेरा के महान मठों में संरक्षित किया गया है जो वर्तमान में दक्षिण भारत में

फिर से स्थापित किया गया है।

उन्होंने आगे बताया मरने के बाद कुछ भी नहीं रहने का जो सामान्य वैज्ञानिक और भौतिकवादी दृष्टिकोण है, वह नैतिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। यदि मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं रहने की बात मान ली जाए तो हमें अपने कार्यों के परिणामों को भुगतने में भी विश्वास करने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने अंत में कहा कि इसके बजाय हमें हर किसी की सेवा करने के तरीके खोजने होंगे।

इसके बाद, कर्नल जिंदल ने परम पावन को उनके संबोधन के लिए आमंत्रित किया। परम पावन ने तिब्बती में सभा को संबोधित किया, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद डॉ. थुबतेन जिनपा ने किया। परम पावन ने संबोधन की शुरुआत बुद्ध शाक्यमुनि की वंदना में एक श्लोक का पाठ करने के साथ की।

परम पावन ने स्पष्ट किया कि बुद्ध की शिक्षा को जो चीज परिभाषित करती है वह प्रतीत्य समुत्पाद की उनकी व्याख्या है। इसके लिए तिब्बती में दो शब्द हैं- 'दस-जंग'। इनमें से दस का अर्थ आश्रित होना और दूसरे जंग का अर्थ होता है- उत्पन्न होने वाला। इससे हमें वास्तविकता का बोध होता है। सब कुछ आश्रित है। कुछ भी स्वतंत्र नहीं है। चीजें अन्य कारकों पर निर्भर रहते हुए उत्पन्न होती हैं। चूंकि कुछ भी स्वतंत्र नहीं है इसलिए सब कुछ निर्भर संबंधों के माध्यम से आता है।

उन्होंने आगे और स्पष्ट करते हुए बताया कि प्रतीत्य समुत्पाद को समझना क्यों महत्वपूर्ण है? वह इसलिए कि जब हमारे पास यह अंतर्दृष्टि नहीं होती है तो हम स्वयं को कुछ पर्याप्त और वास्तविक मानते हैं। बदले में यह 'हम' और 'उन' के बीच अंतर को चिन्हित कर सकता है जो संघर्ष को जन्म देते हैं। हम अपने लोगों के प्रति आसक्ति करते हैं और दूसरों के प्रति घृणा विकसित करते हैं, जिन्हें हम अलग-अलग देखते हैं।

करुणा भी बुद्ध की शिक्षाओं के केंद्र में है। चंद्रकीर्ति अपने 'मध्यम मार्ग प्रवेशिका' की शुरुआत में ही करुणा के प्रति श्रद्धावनत होते हुए इसका संकेत देते हैं। वह करुणा की तुलना नमी वाले स्थल में पड़े एक ऐसे बीज से करते हैं जो बीज को बढ़ने में मदद करती है और अंत में उसका फल प्राप्त होता है।

बुद्ध की शिक्षा का मूल करुणा और प्रज्ञा का संयोजन है और बौद्धों के रूप में हमारा कार्य इन दोनों गुणों को विकसित करना है। 'हम जिन समस्याओं का सामना करते हैं उनमें से कई इस बात से संबंधित होते हैं कि हम वास्तविकता को कैसे देखते हैं। हमारी सोचने की प्रवृत्ति यह होती है कि चीजें जिस रूप में दिखाई देती हैं, उसी रूप में उनका अस्तित्व होता है। हमारे सामने जो दिखाई देता है उसी से हम वास्तविकता का बोध कराते हैं। बुद्ध का शून्यवाद का उपदेश हमें यह समझने में मदद करता है कि हम जो देखते हैं वह वास्तविकता को प्रतिबिंबित नहीं करता है। ऐसा होने पर हम अपने आसक्ति और तृष्णा की भावनाओं पर काबू पा सकते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो मन पवित्र हो जाता है।

एक बौद्ध होने के नाते हमें उस प्रक्रिया पर ध्यान देने की आवश्यकता है जिसके द्वारा हम वस्तुओं की वास्तविकता को ग्रहण करते हैं। यदि हमारी समस्याओं का कोई समाधान प्रस्तुत नहीं किया गया तो केवल पीड़ा पर ध्यान केंद्रित करना मनोबल गिराने वाला होगा। जब हम वास्तविकता में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं तो हम यह भी देख सकते हैं कि हमारे लिए ज्ञानोदय प्राप्त करना संभव है। इसलिए गहन चिंतन के परिणामस्वरूप हमें स्वतंत्रता का बोध होता है।

मैं इसके साथ जूझता रहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि इससे मैं प्रगति कर रहा हूं। चंद्रकीर्ति कहते हैं कि जब आप वास्तविकता में गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में सक्षम होते हैं तो पीड़ित प्राणियों के लिए करुणा स्वाभाविक रूप से पैदा होती है। वह कहते हैं कि अंतर्दृष्टि और करुणा रूपी दो पंखों पर हम मोक्ष की ओर और आगे बढ़ेंगे। मैं अब अपने ८० के दशक के अंत में हूं, लेकिन मैं साधना जारी रखता हूं और तैयारी के साथ मोक्ष मार्ग पर पहुंचने की आकांक्षा रखता हूं।'

परम पावन ने उल्लेख किया कि तिब्बती परंपरा में तंत्र और देवताओं का ध्यान करना भी शामिल है, पर उन्हें लगता है कि जो वास्तव में चित्त पर प्रभाव डालता है वह ज्ञान, वास्तविकता को गहरे देखने की अंतर्दृष्टि और सभी प्राणियों के लिए करुणा की साधना है। ये वे रिवाज हैं जिन्होंने मनुष्य को अपने मन को बदलने में सबसे अधिक सक्षम बनाया है।

उन्होंने खुलासा किया कि चूंकि यह बुद्ध के अनुयायियों का एक समूह है, इसलिए वह यह दिखाने के लिए अपने स्वयं के अनुभव बता रहे हैं कि यदि हम अपने बौद्ध साधना को गंभीरता से लेते हैं, वास्तविकता की गहराई से जांच करते हैं और करुणा का पोषण करते हैं, साथ ही विश्राम और विश्लेषणात्मक ध्यान की प्रथाओं को भी परिष्कृत करते हैं तो यह हमारे दैनंदिन जीवन में बदलाव लाएगा। उन्होंने बताया कि हम सभी ज्ञान के उच्च स्तर की आकांक्षा कर सकते हैं। इसलिए, उन्होंने अपने श्रोताओं से उचित प्रयास करने का आग्रह किया।

उन्होंने आगे अपना वक्तव्य जारी रखते हुए कहा, 'अनुष्ठान महत्वपूर्ण नहीं हैं। हमें जो चाहिए वह है विश्राम और विश्लेषणात्मक ध्यान की साधना, वास्तविकता की समझ और करुणा की साधना। ये उस प्रकार की शिक्षाएं हैं जो आपके भीतर जीवंत हो उठती हैं, इसलिए वे प्रयास करने योग्य हैं।'

'मैं आपको यह भी आश्वासन दे सकता हूं कि करुणा पर साहस के साथ ध्यान देने से आप प्रतिकूल परिस्थितियों को अवसर में बदल सकते हैं।'

'मैं उत्तर-पूर्व तिब्बत में पैदा हुआ था और ल्हासा आया था जहां मैंने बौद्ध आचार्यों के लेखन का अध्ययन किया जिन्होंने ज्ञान और करुणा को विकसित करने के तरीके प्रस्तुत किए। उनकी सलाह का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा। एक अन्य कारक जो बौद्ध धर्म को बाकी धर्मों से अलग करता है वह आंतरिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले साधनों का व्यापक संग्रह है। यह ध्यान साधनाओं में बहुत समृद्ध है जिसका हमारे दिन-प्रतिदिन के आचरण पर प्रभाव पड़ता है। बुद्ध धर्म को अपने जीवन में शामिल करना हमें अपने शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक तरीका है।'

शरत्से खेंसूर जांगछुब छोदेन ने धन्यवाद ज्ञापन किया। उन्होंने परम पावन को उनके वाक्पटु और प्रगतिगामी संबोधन के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, 'आप इस ग्रह पर कई लोगों के लिए एक प्रेरणा हैं, कुछ ऐसी प्रेरणा के, जो आने वाली पीढ़ियों में जारी रहेगी। हमें आपकी सलाह और मार्गदर्शन की आवश्यकता है- कृपया दीर्घायु हों।' उन्होंने प्रोफेसर रॉबर्ट थुरमन और सितागु सयाडॉ को उनके योगदान के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने मंच पर उपस्थित अन्य अतिथियों तथा सभागार में उपस्थित अन्य प्रतिभागियों को आने के लिए धन्यवाद दिया।

मध्याह्न भोजन के पहले तक अंतरराष्ट्रीय बौद्ध प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों के साथ एक बैठक में परम पावन ने दुनिया भर में बौद्ध धर्म में बढ़ती रुचि का उल्लेख किया। इसके कारण के उपयोग को उन्होंने इस समय इसके

आकर्षण का एक हिस्सा बताया।
डॉ. धम्मपिया ने परम पावन को भविष्य में प्राणियों के लाभ के लिए बार-बार यहां आने के लिए अनुरोध किया। परम पावन ने उत्तर दिया कि यह तो उनके द्वारा प्रतिदिन की जाने वाली प्रार्थनाओं के अनुरूप है, विशेष रूप से शांतिदेव के 'बोधिसत्व मार्ग में प्रवेश' से एक छंद का हवाला देते हुए उन्होंने कहा:
जब तक अंतरिक्ष है,
और जब तक संवेदनशील प्राणी रहेंगे,
तब तक मैं भी रहूं
दुनिया के दुख को दूर करने में मदद करने के लिए। १०/५५

परम पावन ने अध्ययन और जांच के महत्व पर बल देने का एक बिंदु बनाया। उन्होंने खुलासा किया कि बुद्ध ने अपने अनुयायियों को प्रोत्साहित किया कि वे अंधविश्वास के आधार पर उनकी शिक्षाओं को स्वीकार न करें बल्कि इसकी अच्छी तरह से जांच और परख कर लें।
उन्होंने स्मरण किया कि आठवीं शताब्दी में तिब्बत के राजा ठिसोंग देचेन ने चीनी ह्वशांग ध्यानियों और भारतीय आचार्य कमलशील के बीच शास्त्रार्थ का आयोजन कराया था। जब राजा ने कमलशील को विजेता घोषित किया और चीनी भिक्षुओं से तिब्बत छोड़ने का अनुरोध किया तो उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि भारतीय परंपरा इस बर्फीले पठार में बौद्ध धर्म की मुख्यधारा बने।
परम पावन ने घोषित किया कि तिब्बती बौद्ध नालंदा के महान दार्शनिक और तर्कशास्त्री शांतरक्षित और उनके शिष्य कमलशील के आभारी हैं कि उन्होंने तर्क और शास्त्रार्थ को महत्व दिया। एक बार फिर अपने स्वयं के अनुभव को याद करते हुए परम पावन ने समझाया कि जब वे तिब्बत में अध्ययन कर रहे थे, तो उन्हें न केवल अपने शिक्षकों से बल्कि परिश्रमी सहायकों के एक दल से भी बहुमूल्य सहायता मिली। अब जब वे उन दिनों को याद करते हैं तो वह वास्तव में खुद को उन सभी का ऋणी महसूस करते हैं। सभा समाप्त होने से पहले उन्होंने बौद्ध प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों को बुद्ध की एक-एक मूर्ति भेंट की। इसके बाद परम पावन ने शिखर सम्मेलन से अपने निवास की ओर प्रस्थान किया।

◆ सिक्योंग इंग्लैंड में अपने कार्यक्रमों के सिलसिले में लंदन पहुंचे

tibet.net, २४ अप्रैल, २०२३

लंदन। तिब्बती लोगों द्वारा लोकतांत्रिक रूप से चुने गए नेता सिक्योंग पेन्पा छेरिंग इंग्लैंड की अपनी आधिकारिक यात्रा के लिए लंदन पहुंचे। इंग्लैंड में उनका कार्यक्रम ०१ मई तक आयोजित किया जाएगा। रविवार दोपहर हीथ्रो हवाई अड्डे पर उतरने पर लंदन स्थित तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि सोनम छेरिंग फ्रासी, केलखंग रिनपोछे, तिब्बती समुदाय ब्रिटेन के अध्यक्ष तेनज़िन कुंगा, अन्य सदस्यों और इंग्लैंड में रह रहे तिब्बतियों ने उनका स्वागत किया।
अपने यूरोप दौरे के इस प्रारंभिक चरण के दौरान, सिक्योंग पेन्पा छेरिंग वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, संसद के सक्रिय तिब्बत समर्थक सदस्यों के साथ-साथ विदेश मामलों, मानव अधिकारों, धर्म की स्वतंत्रता समेत संबंधित संसदीय समिति समूहों के सदस्यों और अन्य दूसरे लोगों से मुलाकात करेंगे। इंग्लैंड दौरे में सिक्योंग की स्कॉटलैंड की यात्रा भी शामिल होगी।
इसके अलावा, सिक्योंग का २५ अप्रैल को ब्रिटिश संसद को संबोधित करने के दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं, जिसकी मेजबानी क्रमशः ऑल पार्टी पार्लियामेंटरी ग्रुप फॉर तिब्बत (तिब्बत के लिए सर्वदलीय संसदीय समूह) और ऑल पार्टी पार्लियामेंटरी ग्रुप फॉर इंटरनेशनल फ्रीडम ऑफ रिलिजन एंड बिलीफ (अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता के लिए सर्वदलीय संसदीय समूह) द्वारा की जाएगी।
सिक्योंग के सार्वजनिक भाषण कार्यक्रम २६ अप्रैल को वेस्टमिंस्टर यूनिवर्सिटी, २७ अप्रैल को एशिया स्कॉटलैंड इंस्टीट्यूट और २८ अप्रैल को एबरडीन यूनिवर्सिटी में भी होंगे। इस यात्रा के दौरान, सिक्योंग नागरिक समाज संगठनों- थिंक-टैंक, मानवाधिकार संगठनों, बौद्ध संगठनों, मीडिया और ब्रिटेन में तिब्बती समुदाय के साथ बातचीत करेंगे।
कल, सिक्योंग लोकतंत्र मंच (टीडीएफ) के प्लेटफॉर्म से 'तिब्बत में चीनी औपनिवेशिक शासन के ७२ साल' विषय पर अपना व्याख्यान देंगे। फोरम की अध्यक्षता लेखक और पूर्व बीबीसी एशिया संवाददाता हम्फ्रे हॉक्सले करेंगे और ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑन तिब्बत के सह-अध्यक्ष और सांसद क्रिस लॉ, एबरडीन विश्वविद्यालय में स्कॉटिश सेंटर फॉर हिमालयन रिसर्च के निदेशक डॉ. मार्टिन मिल्स, वेस्टमिंस्टर विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के प्रमुख और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर दिब्येश आनंद शामिल होंगे। द डेमोक्रेसी फोरम के अध्यक्ष सांसद बैरी गार्डिनर की समापन टिप्पणी के साथ सभा का समापन होगा।
यह कार्यक्रम टीडीएफ फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव होगा।
यह यात्रा सिक्योंग पेन्पा छेरिंग की ब्रिटेन की दूसरी आधिकारिक यात्रा है। सिक्योंग की ब्रिटेन की पहली यात्रा जनवरी २०२३ में हुई थी, जब उन्हें चीन-तिब्बत संघर्ष पर ऑक्सफोर्ड यूनियन सोसाइटी को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया था।

◆ तिब्बत से चोरी हुए बच्चे ११वें पंचेन लामा की ३४वीं जयंती पर डीआईआईआर का बयान

tibet.net, २५ अप्रैल, २०२३

धर्मशाला। आज २५ अप्रैल को तिब्बत के प्रमुख धार्मिक नेताओं में से एक ११वें पंचेन लामा की ३४वीं जयंती है। पंचेन लामा को पूरे परिवार के साथ छह साल की उम्र में अपहरण कर लिया गया और इसके बाद पिछले २७ साल से अधिक समय से वह गुप्त रूप से चीनी हिरासत में हैं। अपने धार्मिक नेता की जयंती दुनिया भर के तिब्बतियों और बौद्धों के लिए पवित्र और

आनंदमय दिन होना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय यह दिन अब चीन द्वारा पंचेन लामा को अपहरण किए जाने और गायब कर दिए जाने का दर्दनाक यादगार बन कर रह गया है।

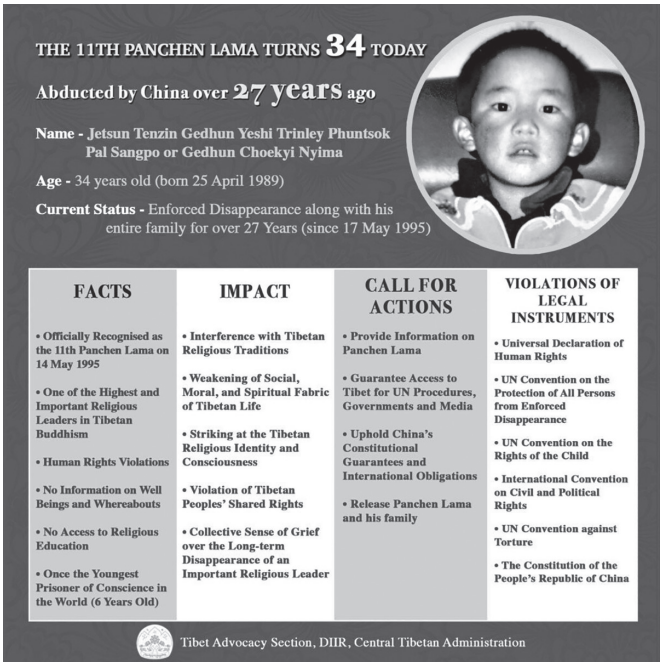

जेट्सन तेनज़िन गेधुन येशी ट्रिनली फुंटसोक पाल संगपो जिन्हें गेधुन चोएक्यी न्यिमा के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म २५ अप्रैल १९८९ को कुंचोक फुंटसोक और डेचेन चोएडन के पुत्र के रूप में तिब्बत के नागचू के लहारी में हुआ था। १४ मई १९९५ को परम पावन दलाई लामा ने छह वर्षीय गेधुन चोएक्यी न्यिमा को स्वर्गीय १०वें पंचेन लामा के ११वें अवतार के रूप में घोषित किया। बीजिंग के अधिकारी चयन प्रक्रिया को नियंत्रित करने की योजना बनाए हुए थे। लेकिन अपनी योजना में बाधा पड़ते देख वे आगबबूला हो गए। परम पावन दलाई लामा की घोषणा के ठीक तीन दिन बाद यानी, १७ मई १९९५ को बच्चे और उसके परिवार के लापता होने की सूचना फैली। इस तरह छह वर्षीय पंचेन लामा तत्कालीन दुनिया के सबसे कम उम्र के राजनीतिक कैदी बन गए।

पंचेन लामाओं को तिब्बत में सबसे सम्मानित धार्मिक नेताओं में से एक माना जाता है, जिनका दलाई लामाओं के साथ विशेष आध्यात्मिक संबंध होता है। इन दोनों धार्मिक नेताओं की तुलना अक्सर तिब्बती बौद्ध आध्यात्मिक आकाश में 'सूर्य और चंद्रमा' की तरह की जाती है। इन दो प्रमुख लामाओं की वंशावली ने न केवल तिब्बतियों के आध्यात्मिक और भौतिक कल्याण में बहुत बड़ा योगदान दिया है, बल्कि तिब्बती लोगों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। महान १४वें दलाई लामा के शब्दों में ११वें पंचेन लामा 'विशेष जिम्मेदारी वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति' हैं और जिन्हें दलाई लामा के काम को आगे बढ़ाना है।

पूरे इतिहास में विभिन्न पंचेन लामाओं ने तिब्बती समाज की बेहतरी के लिए बड़ा योगदान दिया है। उन सभी में सबसे उल्लेखनीय १०वें पंचेन लामा लोबसांग थ्रिनले चोएक्यी ग्यालत्सेन थे, जिन्होंने विशेष रूप से तिब्बती संस्कृति, परंपरा और भाषा को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने विश्वासों में दृढ़, अडिग और साहसी १०वें पंचेन लामा को समकालीन तिब्बत में सबसे प्रभावशाली धर्मगुरुओं में से एक माना जाता था। १०वें पंचेन लामा ने १९६२ में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) के नेताओं को अपनी प्रसिद्ध १४,००० शब्दों (७०,००० वर्णों) का ज्ञापन दिया था। इसमें उन्होंने तिब्बत में तिब्बती संघर्षों को उजागर करते हुए चीनी नेताओं से तिब्बत की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति में सुधार की जिम्मेदारी लेने का आग्रह करना। इस 'अति स्वाभिमानी पंचेन लामा' से नाराज माओ ने उन पर 'प्रतिक्रियावादी शक्ति' होने का आरोप लगाया। पीआरसी के अधिकारियों ने पंचेन लामा को १९६४ से १९७७ तक १३ वर्षों तक कैद में रखा। इस दौरान उन्होंने अत्यधिक यातना और कष्ट सहे। जेल से रिहा होने के बाद जून १९८२ में तिब्बत लौटने पर १०वें पंचेन लामा ने तिब्बती जीवन शैली के पुनर्निर्माण और तिब्बती धर्म और संस्कृति को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए लगातार और साहसपूर्वक अथक काम किया। २८ जनवरी १९८९ को रहस्यमय परिस्थितियों में उनका आकस्मिक निधन हो गया।

बीजिंग द्वारा ११वें पंचेन लामा का अपहरण और पंचेन लामा की पसंद के रूप में ग्यालत्सेन नोरबू का चयन पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित कार्य हैं। इसका उद्देश्य अगले दलाई लामा के चयन को नियंत्रित करना और तिब्बत पर उसके अवैध कब्जे को वैध बनाना है। पिछले २७ वर्षों से पीआरसी द्वारा ११वें पंचेन लामा की अनौपचारिक हिरासत विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संधियों और कानूनों द्वारा संरक्षित कई मानवाधिकार घोषणाओं का घोर उल्लंघन है, जिनमें से कई का सम्मान करने, बढ़ावा देने और रक्षा करने के लिए चीन कानूनी रूप से बाध्य है।

इस अवसर पर डीआईआईआर के सचिव श्री कर्मा चोयिंग ने विभाग का वक्तव्य जारी किया, जिसमें कहा गया है कि 'केंद्रीय तिब्बती प्रशासन का सूचना और अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग (डीआईआईआर) ११वें पंचेन लामा के ३४वें जन्मदिन पर उनकी कुशलता के लिए हार्दिक प्रार्थना करता है। साथ ही, हम दुनिया भर की सरकारों, संसदों, गैर-सरकारी संगठनों, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार निकायों और संस्थाओं, बौद्धों और आम लोगों को पंचेन लामा के लंबे समय से गायब करने को लेकर सामूहिक तौर पर दुख और चिंता प्रकट करते हुए पीआरसी सरकार से अपनी संवैधानिक गारंटी और अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को बनाए रखने और पीआरसी की सरकार से पंचेन लामा और उनके परिवार को तुरंत रिहा करने का आग्रह करने को लेकर लगातार दबाव डालने के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। हम पीआरसी सरकार से तिब्बती लोगों के मौलिक अधिकारों का सम्मान करने और तिब्बती धार्मिक नेताओं और समुदाय के प्रभावशाली व्यक्तियों के जबरन गायब होने की प्रथा को तुरंत रोकने का भी आह्वान करते हैं। जब तक चीन पंचेन लामा के बारे में विश्वसनीय जानकारी प्रदान नहीं करता है और तुरंत उन्हें, उनके परिवार और चाद्रेल रिनपोछे को आज़ाद करते हुए रिहा नहीं करता है, तब तक हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चीन को तिब्बती बौद्ध धर्म और तिब्बती लोगों के धर्म, स्वतंत्रता और विश्वास के निकृष्टतम अनादर के लिए जवाबदेह ठहराने की वकालत करते रहेंगे।'

◆ सिक्योंग ने ब्रिटेन के पार्लियामेंटरी ग्रुप फॉर तिब्बत के साथ चीन-तिब्बत संघर्ष पर चर्चा की और इंटरनेशनल फ्रीडम ऑफ रिलिजन ऑर बिलीफ के समक्ष गवाही दी

tibet.net, २७ अप्रैल, २०२३

धर्मशाला। ब्रिटेन पहुंचने के एक दिन बाद २५ अप्रैल को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने लोकतंत्र के आदर्शों को बढ़ावा देनेवाले अलाभकारी एनजीओ 'डेमोक्रेसी फोरम' द्वारा 'तिब्बत में चीनी औपनिवेशिक शासन के ७२ साल' शीर्षक से आयोजित एक वेबिनार में भाग लिया।

सिक्योंग ने दलाई लामा के पुनर्जन्म के लामाओं और तिब्बतियों के अधिकार पर दावा करने की चीन की अनुचित इच्छा पर प्रकाश डाला और बताया कि कितने युवा तिब्बती अब तक अपनी दुर्दशा के विरोध में आत्मदाह कर चुके हैं। वेबिनार को संबोधित करते हुए सिक्योंग ने उम्मीद जताई कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय उनकी सहायता के लिए आगे आएगा।

ऑल पार्टी पार्लियामेंटरी ग्रुप फॉर तिब्बत (तिब्बत के लिए सर्वदलीय संसदीय समूह या एपीपीजी) के सह-अध्यक्ष, एमपी टिम लॉटन, सांसद केरी मैक्कार्थी और एमपी वेरा हॉबहाउस द्वारा चीन-तिब्बत संघर्ष पर गहन चर्चा के लिए २५ अप्रैल को सिक्योंग की मेजबानी ब्रिटिश संसद में की गई थी। यहां पर सिक्योंगे ने स्पीकर सर लिंडसे हॉयल से संक्षिप्त मुलाकात की और हाउस ऑफ कॉमन्स की कार्यवाही देखी। उन्होंने उसी दिन अपनी आधिकारिक कार्यक्रम के तहत पोर्टकुलिस हाउस में यूके संसद की विदेश मामलों की समिति की अध्यक्ष सांसद एलिसिया किर्न्स से भी मुलाकात की।

इसके अलावा, सिक्योंग ने ब्रिटिश संसद में तिब्बत में धार्मिक स्वतंत्रता पर ब्रिटेन की ऑल पार्टी पार्लियामेंटरी ग्रुप फॉर इंटरनेशनल फ्रीडम ऑफ रिलिजन एंड बिलीफ (एफओआरबी) के समक्ष गवाही दी, जो ब्रिटेन की संसद में सबसे बड़े सर्वदलीय संसदीय समूहों में से एक है। टाशी ल्हुन्पो मठ के मठाधीश श्रद्धेय ज़ेक्याब रिनपोछे; तिब्बती पूर्व राजनीतिक कैदी और दिवंगत तुल्कु तेनज़िन डेलेक रिनपोचे की भतीजी न्यिमा ल्हामो और लंदन स्थित तिब्बत कार्याल के प्रतिनिधि सोनम फ्रैसी सुनवाई के दौरान सिक्योंग के साथ थे।

इंग्लैंड में अपने कार्यक्रमों को समाप्त करने से पहले सिक्योंग ने २६ अप्रैल को वेस्टमिंस्टर यूनिवर्सिटी के फेवी हॉल में मानव अधिकारों, निर्वासन में तिब्बती लोकतंत्र और तिब्बत-चीन संघर्ष से संबंधित मुद्दों पर बात की। इस वार्ता की मेजबानी विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी द्वारा की गई थी और वेस्टमिंस्टर यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के प्रमुख प्रोफेसर दिब्येश आनंद द्वारा आयोजित की गई थी।

◆ क्रॉस पार्टी ग्रुप ऑन तिब्बत के सदस्यों द्वारा स्कॉटिश संसद में सिक्योंग की मेजबानी

tibet.net, २८ अप्रैल, २०२३

स्कॉटलैंड। इंग्लैंड में अपने कार्यक्रमों के समापन के बाद सिक्योंग पेन्पा छेरिंग २७ अप्रैल को स्कॉटिश संसद पहुंचे। वहां स्कॉटिश संसद के सदस्य और तिब्बत पर स्काटिश संसद के सर्वदलीय समूह (स्कॉटिश क्रॉस पार्टी ग्रुप ऑन तिब्बत) के अध्यक्ष रॉस ग्रीर द्वारा सिक्योंग की मेजबानी की गई। स्वागत समारोह में सिक्योंग का स्वागत स्काटिश संसद के सदस्य फ़ैसल चौधरी, स्कॉटिश संसद के सदस्य और संस्कृति, यूरोप और अंतर्राष्ट्रीय विकास मामलों के शैडो मिनिस्टर डोनाल्ड कैमरन और स्कॉटिश संसद के सदस्य पॉलीन मैकनील ने किया।

स्कॉटलैंड की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के दौरान सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने स्कॉटिश राजनीतिक समूहों और अन्य संसद सदस्यों के साथ बातचीत की, जिनमें स्कॉटिश ग्रीन्स पार्टी के सह-नेता सांसद पैट्रिक हार्वी, स्कॉटिश लिबरल डेमोक्रेटिक के नेता सांसद एलेक्स कोल-हैमिल्टन, स्कॉटिश ग्रीन्स के सांसद मार्क रस्केल, स्कॉटिश पार्लियामेंट्स इंटरनेशनल रिलेशन के प्रमुख जेनी चिनम्बिरी और स्कॉटिश पार्लियामेंट में एडिनबर्ग के पार्षद डैन हीप और कायले ओ'नील शामिल थे। इसके अलावा, उन्होंने एडिनबर्ग शहर के लॉर्ड प्रोवोस्ट माननीय पार्षद रॉबर्ट एल्ड्रिज और सिटी चेम्बर्स में एडिनबर्ग काउंसिल के नेता काउंसिलर क्लार कैमी डे से भी मुलाकात की।

सिक्योंग ने क्रॉस पार्टी ग्रुप ऑन तिब्बत के सदस्यों के साथ बैठक के साथ स्कॉटिश संसद में अनेक कार्यक्रमों में शिरकत की। बैठक में क्रॉस पार्टी ग्रुप के अध्यक्ष सांसद रॉस ग्रीर और समूह के सचिव एलेनोर बायरन-रोसेनग्रेन, सांसद मथियास रोसेनग्रेन, डॉ मार्टिन मिल्स, रॉन स्क्रिमेगॉर, लिंडा हेंड्री और कैमरन गैरेट भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में स्कॉटिश हॉगकॉग के लोगों का एक समूह भी शामिल हुआ।

सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने २७ अप्रैल २०२३ को एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में 'तिब्बत: एन अनरिजॉल्व्ड इंटरनेशनल कंफ्लिक्ट (तिब्बत : एक अनसुलझा अंतरराष्ट्रीय संघर्ष)' विषय पर अपनी बात रखी। एशिया स्कॉटलैंड संस्थान द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता लॉर्ड चार्ल्स ब्रूस ने की। कल यानी २८ अप्रैल को लंदन वापस जाने से पहले सिक्योंग एबरडीन विश्वविद्यालय में बोलेंगे।

◆ ऑस्ट्रेलिया के ऑल पार्लियामेंट्री ग्रुप फॉर तिब्बत का प्रतिनिधिमंडल परम पावन दलाई लामा और सीटीए नेतृत्व से मुलाकात की

tibet.net१८ अप्रैल, २०२

धर्मशाला। ऑस्ट्रेलिया के ऑल पार्लियामेंट्री ग्रुप फॉर तिब्बत का चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल सोमवार को चार दिवसीय दौरे पर धर्मशाला पहुंचा।

आज १८ अप्रैल की सुबह प्रतिनिधिमंडल ने परम पावन दलाई लामा के साथ उनके आवास पर मुलाकात की। बैठक में परम पावन ने आज की दुनिया में तिब्बती संस्कृति और धर्म द्वारा अनुमोदित किए गए मूल्यों की प्रासंगिकता पर जोर दिया, जबकि उन मूल्यों को बढ़ावा देने में उनके, विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया की युवा पीढ़ी से योगदान देने की मांग की।

परम पावन के साथ बैठक के बाद प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन का दौरा किया और कैबिनेट सचिवालय में सिक्योंग पेन्पा छेरिंग से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने तिब्बत मुद्दे की वर्तमान स्थिति, चीन-तिब्बत संघर्ष में मध्यम मार्ग दृष्टिकोण के माध्यम से इसके समाधान में सीटीए की स्थिति की मजबूती और निर्वासन में तिब्बतियों के कल्याण को जारी रखने की सीटीए की प्रमुख चिंताओं और प्राथमिकताओं से संबंधित विविध विषयों पर विस्तार से चर्चा की। सिक्योंग के साथ बैठक के बाद प्रतिनिधिमंडल ने तिब्बती संसदीय सचिवालय का दौरा किया और अध्यक्ष खेनपो सोनम तेनफेल और उपाध्यक्ष डोल्मा छेरिंग तेखांग से मुलाकात की। तिब्बत और तिब्बती लोगों के उचित मुद्दे के लिए अपना वास्तविक समर्थन और एकजुटता व्यक्त करने के लिए दौरा करने वाला संसदीय प्रतिनिधिमंडल कल प्रेस कांफ्रेंस भी आयोजित कर रहा है।

सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के सांसदों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सांसद शेरोन क्लेडन (प्रतिनिधि सभा के उपाध्यक्ष) कर रहे हैं और इसमें सीनेटर जेनेट राइस, सांसद सोफी स्कैम्प्स और सांसद सुसान टेम्पलमैन के साथ एटीसी के कार्यकारी अधिकारी ज़ो. बेडफोर्ड शामिल हैं। इस बार धर्मशाला की उनकी यात्रा का समन्वय कैनबरा के तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि कर्मा सिंगे द्वारा किया जा रहा है।

◆ १६वें कशाग ने विजन पेपर- सिक्योरिंग तिब्बत्स फ्यूचर- लाँच किया

tibet.net, १० अप्रैल, २०२३

धर्मशाला। शी-जिनपिंग के नेतृत्व वाली चीनी सरकार ने तिब्बत में तिब्बतियों के चल रहे उत्पीड़न के लिए बार-बार जवाबदेही लेने से इनकार किया है और तिब्बत में सांस्कृतिक संहार की दमनकारी नीति को तीव्रतर करना जारी रखा है। 'राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता' की आड़ में शी सरकार ने तिब्बत में निगरानी और सूचना नियंत्रण पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने के लिए संसाधनों और बलों का व्यापक रूप से दोहन किया है। तिब्बतियों को अक्सर 'अलगाववादी' करार दिया जाता है और उन्हें मनमानी गिरफ्तारी, अपहरण, कारावास और मौत तक के गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। बढ़ी हुई सेंसरशिप के अलावा विदेश में रह रहे तिब्बतियों और विदेशियों- दोनों के लिए तिब्बत तक पहुंच अनिश्चित और कठिन है।

जैसा कि सब लोग जानते हैं कि तिब्बत अपने महत्वपूर्ण मोड़ के करीब है। ऐसे में निर्वासित तिब्बती प्रशासन के नेतृत्व ने अपनी सभी नीतियों और कार्यक्रमों में तिब्बत के भविष्य को सुरक्षित करने को मजबूती से प्राथमिकता दी है। तिब्बत में भाषाई और सांस्कृतिक अधिकारों पर बढ़ते प्रतिबंधों का मुकाबला करने, निर्वासित तिब्बतियों के कल्याण को बढ़ावा देने और सीटीए की प्रशासनिक दक्षता और क्षमता को बढ़ाने को लेकर सिक्योंग पेन्पा छेरिंग की अध्यक्षता वाले १६वें कशाग के नेतृत्व ने आधिकारिक तौर पर आज सुबह यूएसएआईडी, तिब्बत फंड और एनडीआई जैसे प्रमुख फंडिंग संगठनों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में एक विजन पेपर-'सिक्योरिंग तिब्बत्स फ्यूचर्स (तिब्बत के भविष्य की सुरक्षा)' लाँच किया है।

यह सांकेतिक दस्तावेज १६वें कशाग द्वारा पिछले डेढ़ साल के प्रशासन के दौरान दोहराई गई प्रतिबद्धताओं पर आधारित है। यह दस्तावेज निर्वासन में रह रहे तिब्बती समुदाय की जरूरतों को पूरा करते हुए चीन-तिब्बत संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में आगे बढ़ने के मार्ग को गति प्रदान करेगा जो वर्तमान प्रशासन का प्रमुख दोहरा मिशन है। दस्तावेज़ चीन में सकारात्मक विकास लाने और इसे एक जिम्मेदार वैश्विक पक्ष बनाने में तिब्बत के भू-राजनीतिक और सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डालता है।

सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने वरिष्ठ अधिकारियों और सिविल सेवकों की सभा को संबोधित करते हुए कहा, 'अगर हम शी जिनपिंग की मौजूदा नीति का मुकाबला नहीं करते हैं तो यह इस धरती से तिब्बती पहचान को खत्म कर देगा। हम एक धीमी मौत मर रहे हैं।'

उन्होंने दस्तावेज़ में निहित गुणवत्ता सेवाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन और जनता के सामूहिक प्रयास और पारदर्शिता का आह्वान किया। उन्होंने उन सभी लोगों को धन्यवाद दिया, जिन्होंने इस विजन पेपर को आकार देने में योगदान दिया है। भारत में यूएसऐड मिशन निदेशक वीणा रेड्डी ने निर्वासन में तिब्बतियों के सामाजिक एकीकरण और तिब्बती प्रशासन और नागरिक समाज समूहों के व्यवस्थित शासन की सराहना की।

उन्होंने कहा कि 'यूएसऐड को तिब्बतियों और सीटीए के साथ, खासकर भारत और नेपाल में रहने वाले तिब्बती समुदाय की विनम्रता और आत्मनिर्भरता के लिए काम करने पर गर्व है। उन्होंने आगे बाइडेन-हैरिस प्रशासन की अमेरिकी विदेश नीति और विकास का केंद्र में मानव अधिकारों की प्राथमिकता से अवगत कराया।'

◆ चीनी अधिकारी तिब्बत में आत्मदाह करने वाले प्रदर्शनकारियों के रिश्तेदारों के पीछे पड़े हैं

(तिब्बती प्रदर्शनकारियों के रिश्तेदारो को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं और नौकरी के अवसरों से वंचित किया जाता है)

rfa.org / ०५ अप्रैल, २०२३

संग्याल कुंचोक

तिब्बत के दो सूत्रों ने 'रेडियो फ्री एशिया' को बताया कि चीनी अधिकारी उन तिब्बतियों के रिश्तेदारों को परेशान कर रहे हैं और उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, जिन्होंने २००८ के चीनी शासन का विरोध करते हुए अपने को आग के हवाले कर दिया।

सूत्रों ने उदाहरण देते हुए बताया कि ऐसे कई प्रदर्शनकारियों के रिश्तेदार छात्रों को विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा देने से वंचित कर दिया गया है, जबकि कई अन्य को नौकरी के अवसरों से वंचित कर दिया गया है।

लाब्रांग (चीनी : लैबुलेंग) के एक सूत्र ने रेडियो फ्री एशिया की तिब्बती सेवा को बताया, 'यहां एक छात्र है जो २०१३ में आत्मदाह करने वाले व्यक्ति का रिश्तेदार है।' उन्होंने कहा, 'वह यहां इसलिए है कि छात्र को विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए सरकार की ओर से प्रवेश- पत्र देने से वंचित कर दिया गया था और इसलिए वह छात्र कभी विश्वविद्यालय नहीं जा सका। मैंने स्वयं इस बात का गवाह हूं।'

उन्होंने कहा, 'तिब्बतियों ने २००८ की जनक्रांति में भाग लिया था और जो लोग उस जनक्रांति का हिस्सा थे, उनके साथ नौकरी के अवसरों, स्कूलों में और अन्य तरीकों से भेदभाव किया जाता है।' रॉयटर्स के अनुसार, २०१३ में चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में एक पोल पर आत्मदाह के बारे में एक नोटिस चस्पा किया गया था' इसमें आत्मदाह को लेकर 'विचार देने (मास्टरमाइंडिंग), आत्मदाह का समर्थन करने, इसके लिए लोगों को उकसाने और दूसरों को आत्मदाह करने के लिए मजबूर करनेवालों' के बारे में जानकारी देने पर १,००,००० युआन (१६,३१९ अमेरिकी डॉलर) का इनाम देने की घोषणा की गई थी। बीजिंग उन लोगों के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्र कर रहा है, जिन्होंने तिब्बत समर्थक राजनीतिक गतिविधियों, विशेष रूप से १९५९ की तिब्बती जनक्रांति की वर्षगांठ पर २००८ में हुए प्रदर्शनों में भाग लिया। चीनी अधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध- प्रदर्शनों को कुचलने के दौरान ४०० से अधिक तिब्बती मारे गए थे। २००९ के बाद से चीनी कम्युनिस्ट सरकार के दमन के विरोध में १५८ तिब्बतियों ने आत्मदाह कर लिया है। अधिकांश आत्मदाह न्गाबा (चीनी: अबा) और लाब्रांग क्षेत्रों में हुए।

चीनी सरकार प्रदर्शनकारियों और उनके परिवार के सदस्यों के बारे में सारा विवरण आसानी से उपलब्ध ऑनलाइन डेटाबेस में रखती है। न्गाबा के एक अन्य तिब्बती ने कहा कि चीनी सरकार नियमित रूप से प्रदर्शनकारियों के रिश्तेदारों को परेशान करती है।

न्गाबा के सूत्र ने कहा, '२०२२ में चीनी सरकार ने एक तिब्बती को लगातार परेशान किया और उसके बारे में छानबीन करती रही जो न्गाबा में आत्मदाह करने वाले व्यक्ति का भतीजा है। इस तिब्बती पर तिब्बत के बाहर के लोगों से संपर्क करने का आरोप लगाया गया और तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई। इसके बाद उनके परिवार के सदस्यों को मिलने वाली सभी सरकारी सहायता से वंचित कर दिया गया।

लाब्रांग के सूत्र ने कहा कि सरकार पूर्व राजनीतिक कैदियों के प्रति और भी कठोर है। सूत्र ने कहा कि उन लोगों की जांच लगातार चलती ही रहती है, उनका जीवन कभी भी सामान्य नहीं होता है और जब वे दूसरे स्थानों या शहरों में जाते हैं तो उन्हें वहां ठहरने से भी मना कर दिया जाता है।'

'तिब्बतियों को उन गतिविधियों के लिए दोषी ठहराया जाता है, जिन्हें चीनी सरकार अवैध मानती है। ऐसे लोगों के साथ अक्सर भेदभाव किया जाता है और उन्हें उचित चिकित्सा देखभाल से वंचित कर दिया जाता है। उन्हें सरकार से वित्तीय सहायता से भी वंचित किया जाता है।'

◆ सड़कों की सफाई अभियान के दौरान ल्हासा में रेहड़ी-पटरी वाले तिब्बती निशाने पर रहे

(चीन सरकार कई रेहड़ी-पटरी वाले दुकानदारों की आय का एकमात्र स्रोत छीनने की कोशिश कर रही है।)

rfa.org / ०३ अप्रैल, २०२३

चीन सरकार ने शहरों को साफ करने के प्रयास में तिब्बत की राजधानी ल्हासा और उसके आसपास सड़क किनारे रेहड़ लगाने वाले दुकानदारों की वीडियो निगरानी और निरीक्षण बढ़ा दिया है। स्वायत्त क्षेत्र के अंदर के सूत्रों का कहना है कि यह उपक्रम असल में तिब्बती फेरीवालों को सड़कों से हटाने के लिए किया जा रहा है। सूत्रों ने सुरक्षा कारणों से अपनी पहचान बताने से इनकार करते हुए कहा

कि स्थानीय अधिकारियों ने २० मार्च को लगभग ५,६०,००० आबादी वाले शहर में 'क्लीन अप ल्हासा' मुहिम की शुरुआत की जिसमें वे जोखांग या छुगलगखंग मंदिर और उसके आसपास के सभी रेहड़ी वालों और फेरी वालों का निरीक्षण कर रहे हैं।

तिब्बती ल्हासा के बरखोर स्क्वायर में चार मंजिला बौद्ध मंदिर को तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण मंदिर मानते हैं। क्षेत्र के एक तिब्बती ने कहा, 'चीनी अधिकारी उन तिब्बती दुकानदारों को भी प्रतिबंधित कर रहे हैं जो जौ, शा-कम्पो, या सूखे याक, भेड़ के मांस और अन्य खाद्य पदार्थों से बने तिब्बती प्रधान भोजन छम्पा बेचते हैं, उनका आरोप है कि उनके पास भोजन बेचने का उचित बैज नहीं है।

उन्होंने रेडियो फ्री एशिया को बताया, 'हालांकि चीनी सरकार कह रही है कि अभियान का उद्देश्य ल्हासा शहर को स्वच्छ रखना है, लेकिन कोई भी देख सकता है कि इस अभियान के तहत केवल तिब्बती दुकानदारों को निशाना बनाया जा रहा है।' सूत्र ने कहा कि अधिकारी तिब्बती रेहड़ी-पटरी वालों को तिब्बती गीतों की सीडी बेचना बंद करने के लिए भी कह रहे हैं और बिना किसी कारण के उनसे पूछताछ कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 'इससे उन तिब्बतियों को बहुत परेशानी हो रही है, जो सड़क पर अपना जीवन यापन करते हैं।'

सघन निगरानी

चीन तिब्बत पर अपना फौलादी शिकंजा कस कर रखे हुए है। वह तिब्बतियों की राजनीतिक गतिविधियों और बौद्ध उपासक के रूप में सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान की शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित करता है। तिब्बती अक्सर चीनी अधिकारियों द्वारा भेदभाव और मानवाधिकारों के हनन की शिकायत करते हैं और उनका कहना है कि चीन सरकार की नीतियों का उद्देश्य उनकी राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान को मिटा देना है।

इससे पहले हाल में ही ल्हासा और अन्य प्रमुख शहरों में राजनीतिक रूप से संवेदनशील वर्षगांठ से पहले सुरक्षा उपायों में भारी वृद्धि की गई थी। इस दौरान पुलिस ने क्षेत्र के बाहर के लोगों के साथ संपर्क की जांच के लिए लोगों और उनके सेल फोन की बेतरतीब ढंग से जांच की। सरकार का यह नवीनतम इसके बाद ही आया है।

२०२१ में 'सोशल स्ट्रक्चरेशन इन तिब्बतन सोसायटी: एजुकेशन सोसायटी एंड स्प्रिच्युलिटी' शीर्षक से पुस्तक लिखनेवाले ग्याल लो ने कहा, 'चीनी सरकार इन सभी अभियानों के द्वारा अंतत: तिब्बती भाईचारे को दर्शानेवाले प्रत्येक स्थान या व्यवसाय को मिटाना या खत्म करना चाहती है।' ल्हासा पुलिस की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, अब तक अधिकारियों ने क्लीन अप ल्हासा' अभियान के तहत लगभग ३० रेहड़-पटरी वालों से पूछताछ की है और फेरीवालों पर लगातार नजर रख रही है। एक अन्य तिब्बती सूत्र ने कहा, 'कुछ दुकानदार सामान बेचना जारी रखे हुए हैं क्योंकि यह उनकी आजीविका का एकमात्र साधन है।'

उन्होंने कहा कि चीनी अधिकारियों से भिड़ने की कोशिश करने वाले लोगों को हिरासत में लिया गया है, हालांकि गिरफ्तार किए गए लोगों के बारे में या उन्हें कहां रखा जा रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।

उन्होंने कहा, 'चीनी सरकार इस तरह के अभियानों की आड़ में इनमें से कई तिब्बती दुकानदारों के आय का एकमात्र स्रोत छीनने की कोशिश कर रही है।' न्यूयॉर्क में रह रहे एक चीनी वकील जियांग जिओजी ने कहा, 'अभियान का एक संभावित मकसद यह हो सकता है कि ल्हासा को पर्यटन केंद्र होने के मद्देनजर चीनी सरकार अपने उस दावे को बनाए रखना चाहती है कि उसने तिब्बत के आर्थिक विकास में सुधार किया है। उन्होंने आरएफए को बताया, 'वे नहीं चाहते कि पर्यटक सड़क पर तिब्बतियों को फेरी लगाते हुए देखें। वे यह दर्शाना चाहते हैं कि तिब्बती अच्छा और आर्थिक रूप से संतुष्ट जीवन जी रहे हैं।'

◆ संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ चीन द्वारा तिब्बत में व्यापक श्रम शोषण से चिंतित

tibet.net, ११ अप्रैल, २०२३

जिनेवा। तिब्बत में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन, विशेष रूप से व्यापक तौर पर श्रम शोषण से संबंधित गंभीर उल्लंघन पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र के छह विशेषज्ञों के एक समूह ने चीनी सरकार को एक संयुक्त पत्र लिखा है। (एएल सीएचएन १४/२०२२) नंबर वाले ०६ फरवरी २०२३ के इस पत्र को संचार की स्थापित गोपनीयता प्रक्रियाओं के तहत सार्वजनिक किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों के समूह ने चीन से तिब्बतियों की स्थिति, विशेष रूप से तिब्बतियों के व्यापक श्रम शोषण से संबंधित स्थिति को 'स्पष्ट' करने को कहा है। इसमें जबरन श्रम, जबरन श्रम के उद्देश्य से तस्करी, तिब्बती भाषा- धर्म पालन को हाशिए पर रखना, जीवन यापन के तरीके को नियंत्रित करना और कैदियों को जबरन राजनीतिक सिद्धांत का पाठ पढ़ाना, तिब्बत में विचार, विवेक, राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन आदि से संबंधित कार्रवाई हो सकती है। विशेषज्ञों ने उन परिस्थितियों पर भी 'गहरी चिंता' प्रकट की, जिनके तहत तिब्बतियों की राजनीतिक पुनर्शिक्षा हो रही है।

संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों द्वारा चीन को भेजे गए संयुक्त पत्र में तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र में व्यापक श्रमिक स्थानांतरण कार्यक्रम, ग्रामीण श्रमिकों को अकुशल और कम-वेतन वाली औद्योगिक नौकरियों में रखने, कथित तौर पर तिब्बती अल्पसंख्यक भाषाओं, सांस्कृतिक रीति-रिवाजों और धर्म को मिटाए जाने को लेकर विशेष चिंता प्रकट की गई है। पत्र में कहा गया है कि चीनी सरकार ने खुद पुष्टि की है कि '२०१५ से २०२० तक में तिब्बत में २८ लाख से अधिक किसानों और चरवाहों को शहरी क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र से विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में 'स्थानांतरित' किया गया, जिसमें अकेले २०२० में ६,००,००० से अधिक

स्थानान्तरण शामिल हैं।'
संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने चीन से अन्य बातों के साथ-साथ श्रमिक स्थानांतरण कार्यक्रम से संबंधित जानकारी प्रदान करने का आह्वान किया। इनमें तिब्बत में मौजूदा समय में जबरन श्रमिक स्थानांतरण केंद्रों की संख्या और स्थान, श्रमिक स्थानांतरण कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानांतरित विभिन्न नस्लीय तिब्बतियों की संख्या पर अलग-अलग आंकड़े, तथाकथित तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में स्थित व्यवसाय, तिब्बती भाषा के उपयोग पर लगाए गए प्रतिबंध सहित तिब्बती भाषा का उपयोग और इस भाषा में हो रहे शिक्षण, निर्माण या कपड़ा उद्योग जैसे कम वेतन, और कम कुशल नौकरियों में स्थानांतरित किए जा रहे तिब्बती श्रमिकों को दिए जा रहे विशेष 'लाभ' आदि पर भी जानकारी शामिल हैं। इसके अलावा चीन को तिब्बत में सामाजिक स्थिरता के नाम पर ग्रिड प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली के बारे में जानकारी प्रकट करने के लिए कहा गया है।

तिब्बत ब्यूरो जिनेवा के प्रतिनिधि थिनले चुक्की ने संयुक्त पत्र का स्वागत किया है। उन्होंने चीनी शासन के तहत तिब्बतियों की निराशाजनक स्थिति पर ध्यान देने के लिए विशेषज्ञों को धन्यवाद दिया और चीन की सरकार से 'संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों के पत्र पर स्थापित प्रक्रियाओं का सम्मान और समर्थन करते हुए विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने का आग्रह किया। तिब्बत में चीन द्वारा किए गए गंभीर मानवाधिकारों के उल्लंघनों में व्यापक तौर पर श्रमिकों का जबरन स्थानांतरण कार्यक्रम और तिब्बती भाषा का क्षरण शामिल है। साथ ही तिब्बत में अधिकारों के उल्लंघन की लंबी सूची भी शामिल है।

पत्र जारी करने वाले संयुक्त राष्ट्र के छह विशेषज्ञों के समूह में गुलामी- प्रथा के समकालीन रूपों, इसके कारण और परिणाम पर केंद्रित कार्य करनेवाले स्पेशल रिपोर्टियर टोमोया ओबोकाटा, सांस्कृतिक अधिकार के क्षेत्र में काम करनेवाले स्पेशल रिपोर्टियर एलेक्जेंड्रा ज़ांथाकी, विकास के अधिकार पर काम करनेवाले स्पेशल रिपोर्टियर साद अलफरार्गी, अल्पसंख्यक मुद्दों पर काम करनेवाले स्पेशल रिपोर्टियर फर्नांड डी. वेरेनेस, नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, जेनोफोबिया और संबंधित असहिष्णुता के समकालीन रूपों पर काम करनेवाले स्पेशल रिपोर्टियर के.पी. अश्विनी और लोगों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की तस्करी पर काम करनेवाले स्पेशल रिपोर्टियर सियोभान मुल्ली शामिल हैं।'

◆ भारत-तिब्बत मैत्री संघ की बिहार इकाई ने स्वर्गीय रामचंद्र खान स्मृति व्याख्यान के तहत तिब्बत मुक्ति साधना में भारतीयों की भूमिका पर चर्चा की

tibet.net, ११ अप्रैल, २०२३

नई दिल्ली। बिहार में भारत-तिब्बत मैत्री संघ (आईटीएफएस) ने स्वर्गीय रामचंद्र खान स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया। इस व्याख्यान का विषय था- 'तिब्बत मुक्ति साधना में भारतीयों की भूमिका'। स्वर्गीय रामचंद्र खान सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी और आईटीएफएस बिहार के पूर्व अध्यक्ष थे, जिन्होंने तिब्बत मुक्ति साधना में बड़े पैमाने पर योगदान दिया था।
स्मृति व्याख्यान कार्यक्रम की अध्यक्षता आईटीएफएस बिहार के अध्यक्ष डॉ. हरेंद्र कुमार व उपाध्यक्ष डॉ. विकास नारायण उपाध्याय ने की। सभा में मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री व बिहार विधान परिषद सदस्य डॉ. संजय पासवान थे। सभा में डॉ. नवल किशोर चौधरी (पटना में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री), श्रीमती अनुराधा शंकर (बिहार पुलिस सेवा अधिकारी और दिवंगत रामचंद्र खान की बड़ी बेटी), ताशी डेकी (नई दिल्ली में आईटीसीओ की समन्वयक) ने भी शिरकत की।
श्री सुरेन्द्र कुमार ने तिब्बत मुक्ति साधना में स्वर्गीय रामचन्द्र खान के योगदान को याद किया। डॉ. संजय पासवान ने तिब्बत पर चीन के कब्जे और तिब्बत में लागू की जा रही दमनकारी नीतियों की कड़ी निंदा करते हुए परम पावन दलाई लामा के विश्व शांति के संदेश को याद किया।
डॉ. नवल किशोर चौधरी ने चीन द्वारा तिब्बत में बड़े पैमाने पर किए जा रहे पर्यावरण विनाश पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने भारत में चीनी सामानों पर प्रतिबंध लगाने और बहिष्कार करने का भी आह्वान किया। नई दिल्ली स्थित आईटीसीओ की समन्वयक ताशी डेकी ने तिब्बत की स्वतंत्रता में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए तिब्बत मुक्ति साधना में समर्थन के लिए सदस्यों का आभार व्यक्त किया।
प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तावित कुछ प्रमुख मांगों की घोषणा की गईं। इनमें परम पावन दलाई लामा को भारत रत्न प्रदान करने की अपील और भारत-तिब्बत सीमाओं पर चीन के बढ़ते खतरों के खिलाफ मजबूत जवाबी कार्रवाई की मांग की गई थी। स्मारक व्याख्यान में बिहार-आईटीएफएस के सदस्यों ने भाग लिया। इनमें बिहार सर्वोदय बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री प्रमोद शर्मा, चंद्र भूषण, प्रो. रजनीश कुमार, कृष्ण बल्लभ यादव, रघुनंदन शर्मा, राकेश कुमार, सत्येंद्र कुमार, चंद्रशेखर कुमार, सुनीता कुमारी, डॉ. बृजेश कुमार, अरुण कुमार, डॉ. अवध बाबू, तिलेश्वर कुमार, अनिल कुमार सिंह, शाहिद कमल, डॉ मनोज कुमार, राम अवतार प्रसाद, शिवांश विश्वकर्मा और डॉ हरेंद्र कुमार आदि शामिल रहे।

◆ भारत ने विवादित सीमा के पास चीन द्वारा स्थानों के नाम बदलने को खारिज कर दिया

Reuters.com / ०४ अप्रैल २०२३

नई दिल्ली/ बीजिंग। भारत ने मंगलवार को चीन द्वारा अपने पूर्वोत्तर के राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थानों के नाम बदलने की कार्रवाई को खारिज कर दिया। चीन अरुणाचल प्रदेश को अपने क्षेत्र का हिस्सा होने का दावा करता है और इसे दक्षिण तिब्बत कहता है। चीन और भारत ने १९६२ में विवादित ३८०० किलोमीटर (२३६० मील) सीमा

के कुछ हिस्सों पर युद्ध लड़ा था और हाल के वर्षों में पर्वतीय क्षेत्रों में संघर्ष

ने परमाणु-सशस्त्र पड़ोसियों के बीच संबंधों को गंभीर रूप से तनावपूर्ण बना दिया है।

इस मुद्दे को लेकर नवीनतम बयानबाजी का आदान-प्रदान रविवार को शुरू हुआ जब चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि उसने दक्षिणी तिब्बत क्षेत्र में पांच पहाड़ों सहित ११ स्थानों के नामों को 'मानकीकृत' किया है। बयान में एक नक्शा शामिल था जिसमें चीन द्वारा नामित ११ स्थानों को 'ज़ंगनान' या चीनी में दक्षिणी तिब्बत या अरुणाचल प्रदेश में दिखाया गया था। नक्शे में भारत के साथ चीन की सीमा को ब्रह्मपुत्र नदी के ठीक उत्तर में सीमांकित किया गया था। भारत ने इसे खारिज कर दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्विटर पर कहा, 'अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा।' लेकिन चीनी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि नाम परिवर्तन 'पूरी तरह से चीन की संप्रभुता के दायरे में' है।

चीनी प्रवक्ता माओ निंग ने मंगलवार को बीजिंग में एक नियमित मीडिया ब्रीफिंग में कहा, 'दक्षिणी तिब्बत क्षेत्र चीनी क्षेत्र है।' २०२० में उनकी सीमा के पश्चिमी हिस्से में स्थित लद्दाख क्षेत्र में दोनों पक्षों के बीच संघर्ष में कम से कम २४ भारतीय सैनिक मारे गए, लेकिन राजनयिक और सैन्य वार्ता के बाद स्थिति शांत हो गई।

पिछले साल दिसंबर में अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में दोनों पक्षों के सैनिकों के बीच हाथापाई हुई थी। भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि पिछले महीने लद्दाख में स्थिति नाजुक और खतरनाक थी, कुछ जगहों पर सैन्य बल एक-दूसरे के बहुत करीब आ गए थे।

◆ ऑस्ट्रेलियाई संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रेस कांफ्रेंस में तिब्बत मुद्दे पर समर्थन जारी रखने का आश्वासन दिया

tibet.net, १९ अप्रैल, २०२३

धर्मशाला। कैनबरा स्थित तिब्बत सूचना कार्यालय के निमंत्रण पर धर्मशाला का दौरा कर रहे 'ऑस्ट्रेलियन ऑल पार्लियामेंट्री ग्रुप फॉर तिब्बत' के चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने तिब्बती लोगों के प्रति अपना समर्थन और तिब्बत की अनूठी विशेषताओं और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के चीनीकरण अभियान से खतरे में पड़ गई सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में अपनी रुचि व्यक्त करने के लिए एक प्रेस कांफ्रेंस की।

डीआईआईआर सचिव कर्मा चोयिंग ने प्रेस कांफ्रेंस में भाग लेने के लिए मेहमान प्रतिनिधिमंडल की सराहना की और मीडिया के लिए सांसदों और सीनेटर, अर्थात् सांसद शेरोन क्लेडन (प्रतिनिधि सभा के

उपाध्यक्ष), सीनेटर जेनेट राइस, सांसद सोफी स्कैम्प्स और सांसद सुसान टेम्पलमैन का परिचय कराया।

निर्वासित तिब्बती सरकार के नेतृत्व के साथ मुलाकात और धर्मशाला में सरकारी और गैर-सरकारी दोनों संस्थानों के अभी तक के दौरे के अपने सार्थक अनुभव को याद करते हुए प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख नेताओं में से एक सांसद सुसान टेम्पलमैन ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा, 'ऑस्ट्रेलिया ने माना है कि वास्तविक चुनौतियां हैं। तिब्बत में तिब्बतियों और उनकी संस्कृति, शिक्षा, भाषा और तिब्बती जीवन पद्धति पर खतरे हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि यात्रा का उनका लक्ष्य तिब्बत के लिए सर्वदलीय संसदीय मैत्री समूह का प्रतिनिधित्व करने के नाते 'उन मुद्दों के बारे में गहराई से जानकारी प्राप्त करना और यह देखना है कि हम सहायता करने में कितने सक्षम हो सकते हैं और ऑस्ट्रेलियाई मित्र के रूप में क्या कर सकते हैं?

सांसद सुसान टेम्पलमैन के बाद सीनेटर जेनेट राइस ने तिब्बत में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर अपनी और अपने सहयोगियों की सामूहिक चिंताओं को उठाया। जैसे कि चीनी आवासीय स्कूलों में बच्चों को भेजने के लिए तिब्बती अभिभावकों को मजबूर करने को लेकर चिंता। उन्होंने कहा, 'यहाँ धर्मशाला में तिब्बती लोगों के साथ बैठकों के माध्यम से आशा और प्रेरणा की भावना प्राप्त करना अद्भुत रहा है। इसके अलावा, उन्होंने वाशिंगटन में तिब्बत पर विश्व सांसदों के आठवें सम्मेलन के दौरान सिक्योंग पेन्पा छेरिंग और डिप्टी स्पीकर डोल्मा छेरिंग तेखांग के साथ अपनी मुलाकात को याद किया और उन्हें फिर से मिलने को 'पुराने दोस्तों से मिलने' के रूप में परिभाषित किया। अपनी टिप्पणी समाप्त करने से पहले सीनेटर ने सुनिश्चित किया कि 'जब हम ऑस्ट्रेलिया लौटेंगे तो हम तिब्बत के लोगों को न्याय दिलाने के लिए अथक प्रयास करना जारी रखेंगे।' राइस ऑस्ट्रेलिया में तिब्बती लोगों को रहने की समय सीमा बढ़ाने की वकालत कर रही हैं।

ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधि सभा के उपाध्यक्ष सांसद शेरोन क्लेडन ने निर्वासित तिब्बती संसद की उपाध्यक्ष से मिलकर और अच्छी तरह से चल रही तिब्बती लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। चुनौतियों से भरी असामान्य स्थिति के तहत असाधारण संचालन के लिए केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की सराहना करते हुए उन्होंने इसे 'अपनी यादगार

में लोकतंत्र में सबसे असाधारण नवाचार के रूप में परिभाषित किया। उन्होंने तिब्बती सांसदों और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में छिटपुट रूप से रहने के बावजूद सक्रिय भागीदारी और लोकतंत्र में भागीदारी के लिए दुनिया भर में फैले तिब्बतियों को अपनी आदरांजलि अर्पित की और कहा, 'यह लोकतंत्र का एक बेहद सफल मॉडल है'। उन्होंने आगे 'तिब्बती लोगों की असाधारण भावना और विनम्रता' की सराहना की।

सिडनी से सांसद के तौर पर अपने मतदाताओं में बड़े और जीवंत रूप से तिब्बती समुदाय को फलते-फूलते देखकर खुद गौरवान्वित होने के क्षणों को याद करते हुए सांसद सोफी स्कैम्प्स ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा तिब्बती समुदाय को प्रदान की जाने वाली निरंतर सुरक्षा की मांग पर अपनी सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने दो संस्कृतियों के बीच मानवाधिकारों, स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकारों के साझा सिद्धांतों को भी दोहराया।

संवाददाता सम्मेलन के समापन से पहले वक्ताओं ने ऑस्ट्रेलिया में तिब्बतन पॉलिसी एंड सपोर्ट ऐक्ट को पारित करने की संभावना और तिब्बत के लिए एक विशेष समन्वयक की नियुक्ति के मुद्दों पर मीडिया के सवालों का जवाब दिया। साथ ही इन मुद्दों को ऑस्ट्रेलियन ऑल पार्लियामेंट्री ग्रुप फॉर तिब्बत के सदस्यों के बीच चर्चा के लिए प्रस्तावित करने का प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने आश्वासन दिया। इसी तरह उन्होंने एक दिन पहले बैठक के दौरान परम पावन दलाई लामा के साथ जिन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की, उन्हें साझा किया।

प्रेस कांफ्रेंस में प्रतिनिधिमंडल के साथ एटीसी के कार्यकारी अधिकारी ज़ो बेडफोर्ड और प्रतिनिधि कर्मा सिंगे भी थे। सीटीए के प्रवक्ता और डीआईआईआर के अतिरिक्त सचिव तेनज़िन लेक्शे के धन्यवाद ज्ञापन के साथ यह प्रेस कांफ्रेंस समाप्त घोषित की गई।

◆ फ्रांसीसी सीनेट का चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पांच दिवसीय दौरे पर धर्मशाला पहुंचा

tibet.net, २१ अप्रैल, २०२३

धर्मशाला। सीनेटर जैकलीन यूस्टैच-ब्रिनियो के नेतृत्व में फ्रांस की सीनेट का चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पांच दिवसीय दौरे पर गुरुवार को धर्मशाला पहुंचा। शिष्टमंडल ने चीन-तिब्बत संघर्ष और निर्वासन में तिब्बतियों के कल्याण से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट सचिवालय में कल सिक्योंग पेन्पा छेरिंग से मुलाकात की। २१ अप्रैल की सुबह प्रतिनिधिमंडल ने कालोन नोरज़िन डोल्मा और सूचना और अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। कालोन ने तिब्बत में तिब्बतियों की गंभीर दुर्दशा को लगातार उजागर करने और चीन-तिब्बत वार्ता को फिर से शुरू करने के लिए मजबूत समर्थन की वकालत करने के लिए प्रतिनिधिमंडल विशेष रूप से सीनेटर ब्रिनियो का आभार व्यक्त किया।

कालोन के साथ बैठक के बाद प्रतिनिधिमंडल ने तिब्बती संसदीय सचिवालय का दौरा किया और अध्यक्ष खेंपो सोनम तेनफेल और उपाध्यक्ष डोल्मा छेरिंग तेखांग से मुलाकात की। दोनों ने तिब्बती मुद्दे के समर्थन और एकजुटता के लिए प्रतिनिधिमंडल को धन्यवाद दिया। प्रतिनिधियों को तिब्बती समुदाय में लोकतंत्र के विकास, निर्वासन में तिब्बती संसद की संरचना और निर्वासित तिब्बती संसद के कामकाज के बारे में जानकारी दी गई।

सोमवार को प्रतिनिधि परम पावन दलाई लामा से मिलेंगे। परम पावन दिल्ली में दो दिवसीय बौद्ध शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद सोमवार को ही लौटनेवाले हैं। धर्मशाला में अपने प्रवास के दौरान फ्रांसीसी प्रतिनिधियों का विभिन्न तिब्बती- शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक संस्थानों का दौरा करने और धर्मशाला और उसके आसपास के तिब्बती नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विनिमय करने का कार्यक्रम है।

◆ प्रतिनिधि डॉ. आर्य ने जी ७ नेताओं से तिब्बत में अधिकारों के उल्लंघन के लिए चीन की निंदा करने वाले बयान जारी करने की अपील की

tibet.net, १९ अप्रैल, २०२३

टोक्यो। जापान के हिरोशिमा शहर में अगले महीने के शुरू में ही होने वाले जी-७ नेताओं के सम्मेलन के साथ, तिब्बत, उग्यूर, दक्षिणी मंगोलिया और हांगकांग के प्रतिनिधियों ने आज जापानी संसद के निचले सदन में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया। मॉडरेटर फूमी फुरुकावा के अनुसार प्रेस कांफ्रेंस का उद्देश्य जी-७ नेताओं का ध्यान मानवाधिकारों के उल्लंघन की बिगड़ती स्थिति और तिब्बत, उग्यूर, दक्षिणी मंगोलिया और हांगकांग में बढ़ते दमन की ओर आकर्षित करना था।

चीन में मानवाधिकारों के उल्लंघन की निगरानी के लिए जापानी संसदीय कॉकस के महासचिव मित्सुबिशी हिरोमी (चुगोकू जिन्केन क्यूमेई) और जापानी पार्लियामेंटरी ग्रुप फॉर तिब्बत के महासचिव कानूनविद इशिकावा अकीमासा ने प्रेस कांफ्रेंस में भाग लिया।

मित्सुबिशी हिरोमी ने मानवाधिकारों और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के महत्व पर प्रकाश डाला और हाल ही में नागानो में विदेश मंत्रियों की बैठक और लोकतंत्र के सिद्धांत और कानून के शासन को कायम रखने वाली उनकी चर्चाओं का उल्लेख किया।

इशिकावा अकिमासा ने अंतरराष्ट्रीय मानदंडों की सुरक्षा के लिए जापान

की प्रतिबद्धता को दोहराया और तिब्बत, उग्यूर, दक्षिणी मंगोलिया और हांगकांग के लिए समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने जासूसी के झूठे आरोप में चीन द्वारा जापानी नागरिकों की गिरफ्तारी पर प्रकाश डाला।

परम पावन दलाई लामा के संपर्क कार्यालय के प्रतिनिधि

डॉ. आर्य छेवांग ग्यालपो ने प्रेस कांफ्रेंस में तिब्बत में कठिन और दमनकारी स्थिति के बारे में जानकारी दी और बताया कि कैसे शी जिनपिंग के 'राष्ट्रीय पुनर्निर्माण' और 'वन चाइना पॉलिसी (एक चीन नीति)' के नारे के तहत चीन सरकार तिब्बत की संस्कृति, धर्म और कब्जे वाले राष्ट्रों- तिब्बत, उग्यूर और दक्षिणी मंगोलिया की पहचान को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है।

उन्होंने जी- ७ नेतृत्व से आग्रह किया कि वे कब्जे वाले क्षेत्रों में मानवाधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता के लगातार उल्लंघन के लिए चीन की निंदा करते हुए एक कड़ा बयान जारी करें।

जापान-उग्यूर एसोसिएशन के उदा करीम, दक्षिणी मंगोलिया कांग्रेस के ओल्हुन्नुद डाइचिन, वर्ल्ड मंगोलिया पीपुल के ओलानचिमगे और जापान-हांगकांग डेमोक्रेसी एलायंस के सैम यिप ने सीसीपी शासन के तहत अपने-अपने क्षेत्रों में गंभीर परिस्थितियों की जानकारी देते हुए बात की। उन्होंने प्रेस से अनुरोध किया कि सीसीपी द्वारा मानवता के खिलाफ किए जा रहे भयानक अपराध पर अधिक ध्यान दिया जाए। इसके बाद मीडिया के सवालों का जवाब प्रतिनिधियों ने दिया।

चीन को मानवाधिकारों का उल्लंघन रोकने, धार्मिक और भाषा के अधिकारों का दमन रोकने और मैग्निट्स्की कानून लागू करने के लिए एक संयुक्त अपील जारी किया गया और इसे जी-७ नेताओं को सौंपने के अनुरोध के साथ मित्सुबिशी को सौंप दिया गया। इसके बाद इसे प्रेस वालों को भी वितरित किया गया।

सुपर संघ के श्रद्धेय कोबायाशी शुई और श्रद्धेय वाकाओमी ताकाशी ने अपनी एकजुटता दिखाने के लिए प्रेस बैठक में भाग लिया। जापान स्थित तिब्बत कार्यालय के सेल्हा, तिब्बती समुदाय जापान (टीसीजे) के अध्यक्ष तेनज़िन शेरब, और टीसीजे के सोनम डोलकर ने भी सम्मेलन में भाग लिया और तिब्बत हाउस जापान से हाल में प्रकाशित- 'तिब्बत को आपकी मदद की ज़रूरत है'- पुस्तक को वितरित करने में मदद की।

◆ जर्मनी ने तिब्बत में सभी अनिवार्य आवासीय स्कूलों को बंद करने का आह्वान किया

tibet.net, २१ अप्रैल २०२३

जिनेवा। जर्मनी की संघीय सरकार ने मानवाधिकार और मानवीय सहायता संबंधी समिति के साथ २० अप्रैल २०२३ को हुई बैठक के बाद तिब्बत में 'तेजी से बिगड़ती' स्थिति पर चिंता व्यक्त की और सभी अनिवार्य आवासीय स्कूलों को तत्काल बंद करने और तिब्बत में तिब्बती खानाबदोशों के जबरन पुनर्वास के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों के आह्वान का समर्थन किया।

जर्मन संघीय सरकार के विदेश कार्यालय के एक प्रतिनिधि ने तिब्बत में मानवाधिकारों के सुनियोजित उल्लंघन पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने तिब्बत की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों के हालिया निष्कर्षों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया और चीन से अनिवार्य आवासीय स्कूलों को समाप्त करने और तिब्बती खानाबदोशों को जबरन हटाने के कार्यक्रम को रोकने का आह्वान किया। विदेश कार्यालय के प्रतिनिधि ने चीनी सरकार की तिब्बत में तिब्बती भाषा, संस्कृति और धर्म को जबरन आत्मसात करने की नीति पर प्रकाश डाला और कहा कि तिब्बत में आवासीय स्कूलों का उद्देश्य 'तिब्बती भाषा और संस्कृति को दबाना' है।

चीन द्वारा तिब्बत में मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन का विवरण देते हुए जर्मन विदेश कार्यालय के प्रतिनिधि ने जोर देकर कहा कि जर्मनी यह सुनिश्चित करता है कि मानवाधिकारों के उल्लंघन के मुद्दे के प्रति जर्मनी आंख मूंदे हुए नहीं रहेगा।

जिनेवा स्थित तिब्बत ब्यूरो के प्रतिनिधि थिनले चुक्की ने तिब्बती लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जर्मनी की दृढ़ प्रतिज्ञा का स्वागत किया और कहा कि यह 'पूरे यूरोप में एक स्पष्ट संदेश देता है कि चीन शासन के तहत तिब्बत में विकट स्थिति की अब और अनदेखी नहीं की जा सकती है'। उन्होंने चीन से तिब्बत में अपने अत्याचारों को ढ़कने के लिए अरबों खर्च करने के बजाय अपने अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्व को पूरा करने और तिब्बती लोगों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए अंतरराष्ट्रीय आह्वान पर ध्यान देने का आग्रह किया।

◆ विशेषज्ञों ने जी-७ नेताओं से तिब्बत में औपनिवेशिक आवासीय स्कूलों को बंद करने के लिए शी जिनपिंग से अनुरोध करने का आग्रह किया

tibet.net, ०१ अप्रैल २०२३/ चास, विजय क्रांति।

मानवाधिकार विशेषज्ञों ने एक अंतरराष्ट्रीय वेबिनार में तिब्बत में चीन की औपनिवेशिक शासन और तिब्बती सभ्यता के लिए उनके खतरे पर चर्चा की।

नई दिल्ली/ मिलान/ लंदन/ धर्मशाला - ३१ मार्च। दुनिया के विभिन्न हिस्सों के विशेषज्ञों ने जापान के हिरोशिमा शहर में १९-२१ मई तक बैठक करने जा रहे जी-७ के नेताओं से अपील की है कि वे चीनी कब्जे वाले तिब्बत में लगातार बिगड़ती मानवाधिकारों की स्थिति को देखते हुए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से तिब्बत में औपनिवेशिक आवासीय स्कूलों की चल रही परियोजना को तुरंत

रोकने के लिए कहें। इस अंतरराष्ट्रीय वेबिनार में 'चीन द्वारा तिब्बत में औपनिवेशिक तरीके से शासन और तिब्बत की सांस्कृतिक पहचान पर संकट' विषय पर विचार-विमर्श के दौरान हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार (सीईएससीआर) समिति द्वारा उठाए गए विभिन्न मानवाधिकार मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।

बेविनार का आयोजन ३१ मार्च की शाम को सेंटर फॉर हिमालयन एशिया स्टडीज एंड एंगेजमेंट (चास) और तिब्बती यूथ कांग्रेस (टीवाईसी) द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। इस वेबिनार में भाग लेने वाले विशेषज्ञों में ब्रिटेन स्थित 'फ्री-तिब्बत' के नीति और अनुसंधान प्रबंधक जॉन जोन्स, वरिष्ठ इतालवी पत्रकार और मिलान से धर्म पर प्रकाशित होनेवाले बहुभाषा-भाषी समाचार पत्र 'बिटर विंटर' के प्रभारी निदेशक मार्को रेस्पिंटी और धर्मशाला से 'स्टूडेंट्स फॉर ए फ्री तिब्बत इंडिया' की राष्ट्रीय निदेशक सुश्री रिनज़िन चोएडन शामिल हुईं। टीवाईसी के संयुक्त सचिव और वेबिनार के सह-मेजबान छेरिंग चोम्फेल ने धन्यवाद ज्ञापन किया और जेएनयू में राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन के विशेष केंद्र की प्रोफेसर और अंतरराष्ट्रीय संबंधों और सुरक्षा मामलों की विद्वान (सुश्री) आयुषी केतकर ने प्रश्न-उत्तर सत्र का संचालन किया। तिब्बत मामलों के विख्यात विशेषज्ञ और चास के अध्यक्ष विजय क्रांति ने वेबिनार का संचालन किया।

रिनज़िन चोएडन ने विशेष रूप से तिब्बती बच्चों को जबरन आवासीय विद्यालयों में धकेलने के चल रहे चीनी अभियान पर अपने संबोधन को केंद्रित किया। ये आवासीय विद्यालय पूरे तिब्बत में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) द्वारा स्थापित किए गए हैं और चलाए जा रहे हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा ये स्कूल व्यवस्थित रूप से तिब्बत की पहचान को मिटाने के उद्देश्य से तिब्बत की पूरी नई पीढ़ी का ब्रेनवॉश करने के लिए चलाए जा रहे हैं। पहले ही दस लाख से अधिक तिब्बती बच्चों को उनके परिवारों से जबरन उठा कर इन स्कूलों में डाल दिया गया है। यह केवल तिब्बत के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि इसमें एक समृद्ध संस्कृति, जो कि पूरी दुनिया से संबंधित है, का पूरी तरह से सफाया हो जाने की आशंका उठ खड़ी हुई है। संयुक्त राष्ट्र के कुछ मंचों और कुछ देशों की संसदों में उठाई जा रही अंतरराष्ट्रीय चिंताओं पर ध्यान देते हुए उन्होंने कहा, 'हम तिब्बती और तिब्बत के समर्थक पिछले कुछ समय से इस मुद्दे को विभिन्न मंचों पर उठाते रहे हैं। यह संतोष की बात है कि संयुक्त राष्ट्र से जुड़े कुछ मानवाधिकार निकायों ने भी अब इस मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया है।'

रिनज़िन ने बताया कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सत्ता में आने के बाद से तिब्बती पहचान को मिटाने की प्रक्रिया को विशेष गति मिली है। उन्होंने कहा, 'तिब्बत में दशकों से तिब्बती संस्कृति और पहचान को नष्ट करने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन दुर्भाग्य से राष्ट्रपति शी के शासन में यह अभियान और अधिक तेज हो गया है।'

मार्को रेस्पिंटी ने संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति (सीईएससीआर) की हालिया रिपोर्ट का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया, जो इसके हालिया ७३वें सत्र के दौरान ०६ मार्च को प्रकाशित हुई थी। उन्होंने सीईएससीआर द्वारा उठाए गए कई गंभीर मुद्दों की ओर इशारा किया। इनमें तिब्बती खानाबदोश घुमंतू जनजातियों का जबरन पुनर्वास, तिब्बती समाज द्वारा स्वेच्छा से चलाए जा रहे तिब्बती भाषा के स्कूलों को बंद करना, तिब्बती संस्कृति और भाषा को मिटाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान, तिब्बती समाज, विशेष रूप से तिब्बती बच्चों को जबरन आवासीय स्कूल प्रणाली में डालकर समाज का चीनीकरण और तिब्बती लोगों के अन्य मानवाधिकारों का दमन। चीनी शासन द्वारा सीईएससीआर के इन आरोपों को 'झूठ' बताकर उसका खंडन किए जाने पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा, 'पिछले कुछ वर्षों में सीसीपी का पक्ष लेना और उसकी नीतियों के समर्थन में बोलना वास्तव में पीआरसी के कट्टर समर्थकों के लिए भी काफी दुरूह हो गया है। वास्तव में सीसीपी के कुकर्मों को छिपाना असंभव है। यहां तक कि सीसीपी ने भी कई बार अपने स्वयं के अपराधों पर अपने बयानों को बदला। लेकिन कटु सत्य और तथ्य को छुपाना असंभव है और इस स्थिति ने भी पीआरसी की प्रतिक्रियाओं को बहुत अधिक प्रभावित किया है। अपने विरोधियों के साथ-साथ पीड़ित किए गए लोगों को धमकाते हुए आज पीआरसी आरोपों का जवाब सीधे 'तो क्या?' कहकर देती है और यह काफी खतरनाक स्थिति है।

विश्व निकायों द्वारा निकाले गए ऐसे निष्कर्षों के प्रति चीनी शासन के अड़ियल रवैये को रेखांकित करते हुए मार्को ने कहा, 'सीसीपी तिब्बत की सांस्कृतिक पहचान पर तब तक तलवार लटकाए रखेगी और उत्पीड़न जारी रखेगी जब तक कि दुनिया के पास इसे रोकने का कोई साधन नहीं आ जाता है। पर्यवेक्षक के तौर पर मैं यह सुझाव देने की स्थिति में नहीं हूं कि पीआरसी को अधिक मानवीय व्यवहार के लिए मजबूर करने के लिए दुनिया को कौन सा उपाय अपनाना चाहिए। मैं केवल यह सुझाव दे सकता हूं कि जब तक दुनिया पीआरसी के साथ सुविधाजनक व्यापार करने के फैसले लेती रहेगा या सीसीपी की गलत नीतियों के साथ हां में हां मिलाती रहेगी, तब तक तिब्बती और अन्य लोग कष्टों को भोगते रहेंगे।

लंबे समय से चीन पर नजर रख रहे और तिब्बत में मानवाधिकारों की स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे जॉन जोन्स ने तिब्बत में चीनी पुलिस द्वारा तिब्बती आबादी के चल रहे रक्त परीक्षण और डीएनए नमूनों के संग्रह कार्यक्रम का विशेष संदर्भ दिया। उन्होंने बताया कि ब्रिटेन में उनका समूह 'फ्री-तिब्बत' और यूरोप और अमेरिका में कई अन्य तिब्बत समर्थक समूह अमेरिकी कंपनी थर्मो फिशर साइंटिफिक पर चीनी पुलिस विभाग को डीएनए परीक्षण किट की आपूर्ति रोकने का दवाब बना रहे हैं और इस कंपनी के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। उन्होंने कहा, 'अब हम सीधे इस कंपनी के कर्मचारियों से संपर्क कर रहे हैं और इस तरह के बड़े पैमाने पर प्रोफाइलिंग किए जाने से तिब्बती आबादी को होनेवाले खतरों के बारे में आगाह कर रहे हैं और उन्हें संवेदनशील बना रहे हैं। हमारे अभियान का उद्देश्य कर्मचारियों की जमीर को जगाना और इस कंपनी को चीनी सरकार के इस अमानवीय कृत्य में उपकरण बनने से बाज आने के लिए राजी करना है।'

जॉन ने डॉ. ग्याल लो के अनुभव का उल्लेख किया जो तिब्बत के प्रमुख हिमायती और इस विषय के विशेषज्ञ हैं। डॉ. ग्याल लो के अनुभव का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा, 'उन्होंने अपने परिवार में देखा कि कैसे इन आवासीय स्कूलों में भेजे जाने के तीन महीने के भीतर बच्चे केवल चीनी भाषा में ही एक-दूसरे से बात करने लगे, भले ही वे तिब्बती भाषा बोलते हुए बड़े हुए हों। जब बच्चे सप्ताहांत में घर जाते थे तो वे घर में चुप रहते थे, लगभग मेहमानों की तरह बर्ताव करते थे।' तिब्बत में चीन के औपनिवेशिक आवासीय स्कूलों के मुद्दे पर अब अंतरराष्ट्रीय मंचों पर चर्चा होने पर राहत व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, 'यह देखकर खुशी हो रही है

कि टाइम और न्यूजवीक जैसी समाचार पत्रिकाओं और संयुक्त राष्ट्र निकायों ने इस मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया है।' प्रतिभागियों ने आगामी जी-७ शिखर सम्मेलन में भाग लेने जा रहे विश्व के नेताओं से जॉन की उस अपील का समर्थन किया कि वे नेता चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से तिब्बत में इन औपनिवेशिक आवासीय स्कूलों को बंद करने के लिए कहें।

◆ चीन की बढ़ती असुरक्षा की ऐतिहासिक जड़ें और समकालीन अभिव्यक्तियां

tibet.net २० अप्रैल २०२३, शेरप थेरचिन

चीन अपनी वैधता और स्थिरता के लिए आंतरिक और बाहरी चुनौतियों के जटिल जाल में उलझा हुआ है।

ओटावा, १७ अप्रैल, २०२३। हमारे लोकतांत्रिक संस्थानों में चीनी हस्तक्षेप की प्रकृति और उसकी सीमा पर जारी बहस ने कई कनाडाई लोगों को यह सवाल करने के लिए प्रेरित किया है कि चीन ऐसी निर्लज्ज गतिविधि क्यों कर रहा है, जो उसकी अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकती है और अन्य देशों के साथ उसके संबंधों को खराब कर सकती है। हालांकि, इस आचरण से जुड़े रुझानों की गहराई से परीक्षण करने पर इसमें चीन की गहरी असुरक्षा का पता चलता है, जो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) की विदेश नीति निर्माता अभिजात वर्ग के बीच व्याप्त है।

यह असुरक्षा विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होती है, जिसमें चीन का अंतिम साम्राज्यवादी देश होना शामिल है। चीन एकमात्र देश है जिसने कई देशों पर औपनिवेशिक कब्जा कर रखा है। चीन की स्थिति, तिब्बत, पूर्वी तुर्केस्तान और दक्षिणी मंगोलिया जैसे राष्ट्रों पर कब्जा कर उनसे उपनिवेश जैसा बर्ताव उसकी शासन की वैधता को संदिग्ध बनाता है। इसी तरह कम्युनिस्ट चीन की स्थापना की प्रकृति का अधिनायकवादी होना भी उसकी असुरक्षा को बढ़ाता है। इस देश का यह चरित्र अतीत में लाखों लोगों की मौत का कारण बन चुका है। इनमें ग्रेट लीप फॉरवर्ड (१९५८-६२), सांस्कृतिक क्रांति (१९६६-७६) और तियानमेन स्क्वायर नरसंहार (१९८९) जैसे सामाजिक-राजनीतिक अभियानों के दौरान लाखों लोगों का संहार शामिल है। इसके फौलादी पंजे के नीचे कब्जे वाले लोगों के लिए भाषाई, सांस्कृतिक और धार्मिक आत्मनिर्णय के अधिकारों से इनकार बीजिंग की कमजोरियों को भयावह पैमाने तक बढ़ाता है।

उपरोक्त सभी घटनाओं में सबसे महत्वपूर्ण असुरक्षा वह हैं जो पीआरसी के सत्तावादी, एकदलीय शासन से उपजी हैं, जो अपने नागरिकों को आत्म-अभिव्यक्ति के बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकारों से भी वंचित करती हैं। शक्ति और प्रभाव के अहंकार में चूर चीन की विदेश नीति पार्टी और देश के इतिहास को फिर से लिखने और चीनी व्यवहार के इर्द-गिर्द पूरी परिस्थिति को नियंत्रित करने के लिए बेताब है। मुक्त और लोकतांत्रिक जीवन जीने का क्या मतलब है, इस बारे में बढ़ती जागरूकता शासन की कई महान दीवारों और फायरवॉल में और दरारें डाल रही हैं। यह इसलिए हो रहा है कि चीन की विशाल आबादी विदेश की यात्रा करती है और वहां अध्ययन कर रही है।

चीन की उल्लेखनीय वृद्धि और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्ति के रूप में पुनर्स्थापित होने और इसके सबसे धनी अभिजात वर्ग द्वारा विलासिता की वस्तुओं के भारी उपयोग के बावजूद देश में बेचैनी की भावना बनी हुई है। पीआरसी ऐतिहासिक समस्याओं से घिर गया है। आधुनिक पार्टी अपनी आक्रामक कार्रवाइयों को सही ठहराने के बहाने 'चीन के राष्ट्रीय कायाकल्प' की धारणा पर भरोसा करती है। यह अवधारणा चीन में मौजूद सभी राष्ट्रीयताओं और लोगों को वर्चस्ववादी हान संस्कृति में विलीन करने और सीसीपी के एकदलीय शासन द्वारा उन सबको संरक्षित करने में निहित है।

अंतरराष्ट्रीय समुदाय के पास चीन की बढ़ती असुरक्षा को पहचानने और उसे संवाद कायम के कई अवसर मौजूद हैं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय समुदाय चीन के साथ दूसरे तरीके से संपर्क करने को अहम मान रहा है। वह चीन के साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापार और व्यापार से जुड़े लाभ के अवसरों से उत्पन्न मौके का फायदा उठाने को आतुर है। नतीजतन उत्साहित पीआरसी अब दक्षिण चीन सागर में अपने क्षेत्रीय दावों पर जोर दे रही है, भारत-तिब्बत सीमा क्षेत्रों पर अतिक्रमण कर रही है, नेपाल और मंगोलिया में अनुचित प्रभाव डाल रहा है और हांगकांग की स्वायत्तता की गारंटी का उल्लंघन कर रहा है। घरेलू तौर पर, पीआरसी उइगरों के सामूहिक कारावास, तिब्बती खानाबदोशों के जबरन पुनर्वास और कब्जे वाले क्षेत्रों में अन्य आत्मसातवादी नीतियों के कार्यान्वयन को आगे बढ़ा रहा है।

चीन की सख्ती का असर उसके पड़ोसी एशियाई देशों से आगे बढ़ गया है। वह अब ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों में उनके लोकतांत्रिक संस्थानों में घुसपैठ के माध्यम से पहुंच रहा है। यदि खुफिया जानकारी लीक करने वालों द्वारा जोखिम उठाकर इन हस्तक्षेपों को उजागर नहीं किया जाता तो शायद हम चीन की विस्तारवादी नीतियों पर उचित ध्यान नहीं दे पाते जो इसकी अंतर्निहित असुरक्षा की भावना में निहित हैं।

उदाहरण के लिए तिब्बती आध्यात्मिक धर्मगुरु परम पावन १४वें दलाई लामा के साथ सीसीपी के व्यवहार को ही लें। कोई यह पूछ सकता है कि दुनिया की सबसे बड़ी सेना या दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के लिए शांति और करुणा का संदेश देने के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध एक भिक्षु क्या खतरा पैदा कर सकता है- एक ऐसा व्यक्ति, जिसके पास न कोई सेना है न कोई सत्ता। जिसने अपने जीवन का अधिकांश समय पड़ोसी भारत में निर्वासन में बिताया है। फिर भी उसके हर कदम पर बारीकी से नजर रखी जाती है और विभिन्न जबरन और गुप्त रणनीतियों के माध्यम से उसे अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अलग करने के लिए अथक प्रयास किए जाते हैं।

सीसीपी की असुरक्षा इतनी गहरी है कि परम पावन न केवल इस जीवनकाल में उनकी वैधता को खतरे में डालते हैं, बल्कि अपने अगले जीवनकाल में भी। विडंबना की भयावहता तब और अधिक उजागर होती है जब आधिकारिक तौर पर साम्यवादी और नास्तिक देश चीन ने तिब्बती बौद्ध धर्म के अगले धर्मगुरु की पहचान करने का अधिकार भी अपने पास जबरन रख लिया है। कुल मिलाकर केवल चीन में ही किसी को पुनर्जन्म लेने के लिए नौकरशाही की अनुमति की आवश्यकता होती है।

वैश्विक लोकतांत्रिक संस्थानों में इस तरह से निर्मित चीनी हस्तक्षेप का परीक्षण आज की पीआरसी की असुरक्षा पर और प्रकाश डालता है। इस असुरक्षा की ऐतिहासिक जड़ें अब अधिनायकवादी नियंत्रण, लोकतांत्रिक अधिकार देने से इनकार और अंतरराष्ट्रीय समझ पर हावी होने के प्रयासों जैसे विभिन्न रूपों में देखी जा सकती हैं।

अपने प्रभावशाली आर्थिक और सैन्य शक्ति के बावजूद चीन अपनी वैधता और स्थिरता के लिए आंतरिक और बाहरी चुनौतियों के एक जटिल जाल में उलझा हुआ है। जैसा कि विश्व समुदाय चीन की कार्रवाइयों से उत्पन्न स्थितियों से जूझ रहा है, उसे पीआरसी की अनिश्चित नीतियों और व्यवहारों को आकार देने में इन असुरक्षाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानना चाहिए। शेरप थेरचिन कनाडा तिब्बत समिति के कार्यकारी निदेशक हैं।

◆ संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों का कहना है कि चीन द्वारा 'व्यावसायिक प्रशिक्षण' तिब्बती पहचान को खतरे में डालनेवाला और तिब्बत में जबरन श्रम के खतरे वाला है

tibet.net, २८ अप्रैल, २०२३

जिनेवा। संयुक्त राष्ट्र के छह विशेषज्ञों के एक समूह ने संयुक्त रूप से २७ अप्रैल २०२३ को एक प्रेस विज्ञप्ति में चीन द्वारा तिब्बत में चलाए जा रहे तथाकथित 'व्यावसायिक प्रशिक्षण' और जबरन श्रमिक स्थानांतरण कार्यक्रमों पर चिंता व्यक्त की। इस मामले को लेकर समूह ने चीनी सरकार को संयुक्त पत्र भेजा है।

विशेषज्ञों ने कहा कि इन कार्यक्रमों का इस्तेमाल 'तिब्बती धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को कमजोर करने, तिब्बतियों की निगरानी करने और राजनीतिक रूप से उन्हें उकसाने के लिए बहाने के रूप में किया जा रहा है'। विशेषज्ञों ने यह भी चेतावनी दी थी कि इस तरह के कार्यक्रमों से जबरन श्रम की स्थिति पैदा हो सकती है।

संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने कहा कि २०१५ के बाद से हजारों तिब्बतियों को उनके पारंपरिक रूप से स्थापित जीवन चर्या से जबरन कम-कुशल और कम वेतन वाले श्रमिक के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया है। 'कार्यक्रम को स्वैच्छिक बताया गया है, लेकिन व्यवहार में यह जबरन थोपी गई प्रतीत होती है।'

विशेषज्ञों ने कहा कि श्रमिक स्थानांतरण कार्यक्रम तथाकथित व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों को एक नेटवर्क द्वारा संचालित किया जा रहा है, जो पेशेवर कौशल विकसित करने पर कम ध्यान केंद्रित करते हैं, जबिक सैन्यीकृत वातावरण में सांस्कृतिक और राजनीतिक सिद्धांतों पर अधिक जोर डालते हैं। इसके अलावा, विशेषज्ञों ने इस मुद्दे का विशेष रूप से उल्लेख किया कि कार्यक्रम में तिब्बतियों को तिब्बती भाषा का उपयोग करने से रोक दिया गया है और उनकी धार्मिक पहचान की अभिव्यक्ति के किसी भी रूप से मना किया गया है। इन दोनों को 'अधिकारियों द्वारा गरीबी उन्मूलन में बाधा' के रूप में देखा जाता है।

चीन का दावा है कि तथाकथित व्यावसायिक प्रशिक्षण और श्रमिक स्थानांतरण जीवन स्थितियों में सुधार पर केंद्रित है।

जबकि, संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने स्पष्ट रूप से अंतर्निहित मुद्दों का विस्तृत विवरण दिया है कि कार्यक्रम 'तिब्बतियों को और अधिक गरीबी को ओर ढकेलता है और जबरन श्रमिक बनाने की ओर ले जाता है।'

संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने चीन से आह्वान किया कि वह तिब्बतियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और श्रमिक स्थानांतरण कार्यक्रमों से बाहर निकलने के लिए किए गए उपायों को स्पष्ट करे, तिब्बतियों के रोजगार के नए स्थानों में काम करने की स्थिति की निगरानी करे और तिब्बती धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक पहचान के लिए सम्मान सुनिश्चित करे। विशेषज्ञों ने चीनी सरकार से यह भी आग्रह किया कि वह अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के पालन में जबरन श्रम और तस्करी को रोकने के लिए, और इस तरह के अत्याचारों के पीड़ितों के लिए उपचार और मुआवजा सुनिश्चित करने के बारे में किए गए उपायों के बारे में भी स्थिति को स्पष्ट करे।

संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ समूह की प्रेस विज्ञप्ति का स्वागत करते हुए तिब्बत ब्यूरो-जिनेवा के प्रतिनिधि थिनले चुक्की ने संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों को अपने अनुरोध को स्वीकार करने और तिब्बत में स्थिति की बारीकी से निगरानी करने के लिए धन्यवाद दिया। प्रतिनिधि थिनले ने टिप्पणी की, 'विशेषज्ञों का विस्तृत पत्र और जबरन श्रम पर प्रेस विज्ञप्ति जिसमें तिब्बतियों को कम-कुशल और कम-वेतन वाले काम में ढकेला जाता है, स्पष्ट रूप से चीनी सरकार के 'तिब्बत में विकास' के हताश आख्यान को खारिज करता है। यह संयुक्त राष्ट्र सहित अंतरराष्ट्रीय समुदाय का दायित्व बनता है और सदस्य देश 'तिब्बत में विकास' विशेष रूप से किसके लिए विकास और किस कीमत पर विकास पर चीन से सवाल कर सकते हैं।'

संयुक्त राष्ट्र के छह विशेषज्ञों के समूह में गुलामी- प्रथा के समकालीन रूपों, इसके कारण और परिणाम पर केंद्रित कार्य करनेवाले स्पेशल रिपोर्टियर टोमोया ओबोकाटा, सांस्कृतिक अधिकार के क्षेत्र में काम करनेवाले स्पेशल रिपोर्टियर एलेक्जेंड्रा ज़ांथाकी, विकास के अधिकार पर काम करनेवाले स्पेशल रिपोर्टियर साद अलफरार्गी, अल्पसंख्यक मुद्दों पर काम करनेवाले स्पेशल रिपोर्टियर फर्नांड डी वेरेनेस, नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, जेनोफोबिया और संबंधित असहिष्णुता के समकालीन रूपों पर काम करनेवाले स्पेशल रिपोर्टियर के.पी. अश्विनी और लोगों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की तस्करी पर काम करनेवाले स्पेशल रिपोर्टियर सियोभान मुल्ली शामिल हैं।'

IMPORTANT NOTICE

Dear Readers,

Firstly, I would like to express my heartfelt appreciation for the overwhelming response and support that we have received from you since the launch of Tibbat Desh Magazine.
Tibbat Desh Magazine is the only monthly Hindi Magazine on current affairs of Tibet which includes news on teachings of His Holiness the Dalai Lama, Current grave situations inside Tibet, Events & activities in Exile and of the Tibetan Freedom movement across the globe.
You must be aware, for the past 2 years, we have been receiving complaints about delay and not obtaining the Tibbat Desh magazine on time to our readers. And also we found that many of our readers either have shifted or changed their existing postal address. Therefore to review the mailing address, we request you to assist us in providing the current postal address at the below mentioned address or email.
We would also request our readers to send their feedbacks and suggestions about the magazine.

Yours Sincerely,

Tashi Dekyi
Deputy Coordinator
India Tibet Coordination Office

आवश्यक सूचना

प्रिय पाठकों,

सबसे पहले में, आप सभी का बहुत अभार व्यक्त करता हूं कि जब से तिब्बत देश मासिक पत्रिका का विमोचन हुआ आप लोगों का निरंतर समर्थन एवं शानदर भागीदारी रहा है।
तिब्बत देश, तिब्बत की पहली हिन्दी समाचार पत्रिका है, जो तिब्बत के भीतर हो रहे चीनी दमनकारी और क्रूर नीति तथा विश्व स्तर पर परमपावन दलाई लामा के मार्गदर्शन में तिब्बती आंदोलन के बारे में भारत के सरकार और लोगों में समर्थन एवं जानकारी उपलब्ध कराना है।
आप सभी को ज्ञात है कि, पिछले दो वर्षों से, हमारे पठकों का बहुत सारे शिकायतों हमारे इस कार्यलय में प्राप्त हुआ, जिनमें कई का यह कहना था कि उनको तिब्बत देश मिल नही रहा है। साथ ही हमें यह भी जानकारी मिली है कि बहुत सारे पठकों का पता एवं आवास बदल गया है या वहां से रवाना हो चुका है।
इसलिए हम इस पत्रिका का इस बार समीक्षा कर रहे है। और आप सभी से यह निवेदन करता हूं कि अगर आपको तिब्बत देश पत्रिका प्राप्त हो रहे है तो उसकी पुष्टी हमे तुरन्त देने की कष्ट करें। आप इसकी पुष्टी हमारे नीछे लिखे गये पता या ई–मेल पर भेज सकते है।
अतः तिब्बत देश पत्रिका के संदर्भ में अपना राय एवं सुझाव हमे समय समय पर भेजने की कष्ट करें।

सादर आपका

ताशी देकि
उप–समन्वयक, भारत तिब्बत समन्वय केंद्र
नई दिल्ली

कार्यलय पताः भारत तिब्बत समन्वय केंद्र, एच–10, द्वितीय मंजील, लाजपत नगर–03, नई दिल्ली–110024
फोनः 011–29830578
ई–मेलः indiatibet7@gmail.com , coordinator@indiatibet.net

ऑस्ट्रेलियाई संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रेस कांफ्रेंस में तिब्बत मुद्दे पर समर्थन जारी रखने का आश्वासन दिया।

प्रतिनिधि डॉ. आर्य ने जी ७ नेताओं से तिब्बत में अधिकारों के उल्लंघन के लिए चीन की निंदा करने वाले बयान जारी करने की अपील की